● वर्ष-5

● अंक-166

रायपुर, बुधवार
25 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2026-27 का 1.72 लाख करोड़ का बजट संकल्प थीम पर पेश किया। जिसमें एआई, खेल उत्कर्ष, पर्यटन, अधोसंरचना, स्टार्टअप, स्वास्थ्य-शिक्षा पर बड़े प्रावधान और आदिवासी क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी, ओलंपिक जैसे ऐलान से विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखी गई।

पांच मिशन पर फोकस

इस बार के बजट में सरकार ने पांच मिशन पर फोकस किया है। ताकि विकास को रफ्तार दिया जा सके। इसमें...

- मुख्यमंत्री एआई मिशन
- मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
- मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
- मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
- मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं एनआईपीयूएन मिशन

साय सरकार के संकल्प का बजट

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट पेश

- **कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, 100 करोड़ मिले**
- **जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़**
- **युवाओं के लिए कुल 1,097 करोड़**
- **युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़**

रायपुर।रायपुर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। यह बजट एक लाख 72 हजार करोड़ रुपये का है और 'संकल्प' थीम पर आधारित है। बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

बजट में महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कृषि उन्नत योजना के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है। वहीं, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वन संरक्षण के लिए 913 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इसके साथ ही नक्सलियों के गढ़ को एजुकेशन का हब बनाने का फैसला लिया गया

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के दौरान कहा कि डेयरी समग्र विकास योजना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम है। हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य किया गया है।साय सरकार का तीसरा बजट %ज्ञान% और %गति% के बाद %संकल्प% के थीम पर आधारित है। जिसका अर्थ समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक है।छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्माण सशक्त माताएं और स्वस्थ, शिक्षित बच्चे करेंगे। महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट की मुख्य बातें

- बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी।
- दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती।
- बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान।
- बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान।
- बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज।
- आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए।
- मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे।
- जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा।
- राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होगा।
- कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज।
- मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान।
- 10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा।
- 206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में खाद लैब का होगा निर्माण।
- जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।
- रायपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए सर्वे एजेंसी तय।
- एयरपोर्ट विकास के लिए सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान।
- नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
- 4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
- सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 5 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान।
- मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपए।
- एनएचएम के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- पीडब्ल्यूडी के लिए 9450 करोड़ का प्रावधान।
- कालेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- 25 कालेज भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए।
- विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ रुपए का प्रावधान।

प्रदेश के विकास को नई गति देगा बजट : मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत किए जा रहे राज्य के बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

उन्होंने कहा कि नवीन विधानसभा भवन में प्रस्तुत होने जा रहा हमारी सरकार का यह तीसरा बजट विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार के विज़न को नई मजबूती प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का यह बजट समावेशी विकास, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमजन के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय संकल्प को केंद्र में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रदेश के ÷सुशासन से समृद्धि÷ मॉडल को मजबूत आधार प्रदान करेगा और विकास की गति को और तेज करेगा। यह बजट राज्य के बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन, कृषि उन्नयन, सामाजिक सुरक्षा तथा मानव संसाधन विकास को नई दिशा देगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है और यह बजट उस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बजट से प्रदेश आत्मनिर्भरता, आर्थिक प्रगति और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा।मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेशवासियों को आगामी बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित होगा।

मील का पत्थर साबित होगा बजट संकल्प : नेताम

रायपुर। कृषि और आदिम जाति विकास मंत्री राम विचार नेताम ने वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी द्वारा सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट 'संकल्प' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट संकल्प राज्य के किसानों गरीबों और कमजोर

वर्गों के विकास के लिए मील का पत्थर का साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य की चहुमुखी विकास हो रहा है। विगत वर्षों में प्रस्तुत बजट, ज्ञान, गति के बाद अब संकल्प राज्य के उत्तरोतर विकास के लिए राह आसान करेगी। इसके साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत /2047 की संकल्पों को पूरा करने में भी सहायक होगी।मंत्री श्री नेताम ने कहा कि यह बजट राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ कृषि को मजबूत करने वाला है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करेगा। जनजातीय सुरगुड़ी स्टूडियो के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

भाजपा नेताओं ने किया स्वागत

छत्तीसगढ़ सरकार के वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सत्ता पक्ष ने इसे राज्य के समग्र और संतुलित विकास का दस्तावेज बताया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह बजट गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित है।उन्होंने बताया कि पहले वर्ष की थीम 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) और पिछले वर्ष की 'गति' (गुड गवर्नेंस, एक्सीलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) को आगे बढ़ाते हुए इस बार 'संकल्प' (समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक) की अवधारणा को आधार बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के लिए 9,451 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। साव ने कहा कि बीते 25 वर्षों में बजट में 30 गुना वृद्धि ऐतिहासिक है और इससे शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, सड़क निर्माण और आधुनिक शहरी नियोजन को नई गति मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रति आभार जताया।वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बजट को दूरदर्शी और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट निवेश को परिणामों में बदलने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। उन्होंने कृषक उन्नति योजना, सिंचाई परियोजनाओं, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन और 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत अधोसंरचना निवेश को रोजगार सृजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया।

भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पाण्डेय ने बजट को सर्वहितैषी और सर्वसमावेशी बताते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

यह बजट हर वर्ग के लिए बेहतर

छत्तीसगढ़ के बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली ऐतिहासिक प्राथमिकता पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि यह इस सरकार का तीसरा बजट है, जो प्रदेश की 3 करोड़ जनता के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए समर्पित है।

पिछले दो वर्षों में हासिल विकास की गति को यह बजट और तेज करने तथा छत्तीसगढ़ अंजोर, 2047 के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का संकल्प है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए लाभदायक और हर वर्ग के लिए बेहतर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री की वित्तीय प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य विभाग को व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आमजन को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य के शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय ऐतिहासिक है।

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बजट को सराहा

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बजट को लेकर कहा कि रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मेगा परीक्षा केंद्र, खाद लैब, दृष्टिबाधित शाला के लिए 2.15 करोड़ का प्रावधान और देवभवन स्वामी विवेकानंद निवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा राजधानी को शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक दृष्टि से नई पहचान दिलाएगी। इसके साथ ही तेलीबांधा थाना का नवीनीकरण और मेकाहारा में एआई तकनीक का उपयोग प्रशासनिक और तकनीकी सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। युवाओं के लिए बजट में रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन तथा मुख्यमंत्री एआई मिशन की घोषणा की गई है। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करेगा। यह प्रावधान युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीक में आगे बढ़ने का ठोस प्रयास है। आपको बता दें कि ये विष्णु देव साय सरकार का तीसरा बजट है। सरकार का पहला बजट ज्ञान (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) थीम पर आधारित था, जबकि पिछले साल यह गति (गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर केंद्रित था।

शिक्षा को विकास की मुख्यधारा में रखते हुए दूरदर्शी प्रावधान

रायपुर। राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में शिक्षा और ग्रामोद्योग को विकास की मुख्यधारा में रखते हुए दूरदर्शी एवं जनकल्याणकारी प्रावधान किए हैं। विभागीय मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट प्रदेश की मानव पूंजी को सशक्त बनाने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण अवसर प्रदान करने और पारंपरिक कारीगरों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है, समग्र विकास, सशक्त नागरिक और आत्मनिर्भर प्रदेश।

मॉडल स्कूलों से उत्कृष्ट शिक्षा की ओर बढ़ता प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और अधोसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु पीएम-श्री योजना के अंतर्गत लगभग 350 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके प्रथम चरण में 150 विद्यालयों का चयन किया गया है तथा इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिन विद्यालयों में प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक एकीकृत परिसर हैं, वहां आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण का विकास सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को समग्र और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा मिल सके।

हर बच्चे को सुरक्षित भवन, सुदृढ़ आधारभूत संरचना राज्य सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश में

कोई भी विद्यालय भवन-विहीन न रहे। बजट में 500 प्राथमिक, 100 मिडिल, 50 हाई स्कूल और 50 हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों के निर्माण हेतु कुल 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल न केवल छात्रों को सुरक्षित और अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को भी सुदृढ़ बनाएगी। साथ ही, एनसीसी विद्यार्थियों के स्वल्पाहार की राशि को दोगुना करने के निर्णय युवाओं के मनोबल और अनुशासन को प्रोत्साहित करेगा।

बस्तर में शिक्षा का नया अध्याय

स्थापित होंगी दो एजुकेशन सिटी दंतेवाड़ा के सफल अनुभव के आधार पर अब अबूझमाड़ और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन एजुकेशन सिटी में स्कूल, आईटीआई, प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास, शिक्षक आवास सहित संपूर्ण शैक्षणिक इको-सिस्टम विकसित किया जाएगा। यह पहल बस्तर क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को शिक्षा और अवसर के केंद्र में परिवर्तित करेगी। हस्तशिल्प को वैश्विक पहचान, कारीगरों को नया बाजार ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य सरकार हस्तशिल्प को आजीविका सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम मानते हुए ठोस कदम उठा रही है। ढोकरा आर्ट, बांस कला और माटी कला से जुड़े हजारों परिवारों की आय में वृद्धि के लिए देश के पांच प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट पर शो-रूम स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलेगा। साथ ही, हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि उनके उत्पादों को व्यापक बाजार मिल सके। यूनिटी मॉल और ग्लेजिंग यूनिट से मिलेगा आधुनिक विपणन मंच रायपुर में यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए बजट में 93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो राज्य के हस्तशिल्प उत्पादों को आधुनिक और स्थायी विपणन मंच प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, कुनकुरी के ग्राम गोरिया में 2 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से ग्लेजिंग यूनिट स्थापित की जाएगी, जिससे माटी शिल्पकला को आधुनिक डिजाइन और बाजार उन्मुख स्वरूप मिलेगा। शासन के इस पहल से पारंपरिक कारीगरों के कौशल को नई पहचान मिलेगी और उनके जीवन स्तर में ठोस सुधार सुनिश्चित होगा। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह बजट 2026-27 शिक्षा, कौशल विकास और पारंपरिक उद्योगों को सशक्त बनाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर कारीगर को सम्मानजनक आजीविका का अवसर मिले, यही विकसित और समावेशी प्रदेश की आधारशिला है।

माओवादी संगठन को बड़ा झटका

पहली बार देवजी समेत दो केंद्रीय स्तर के नेताओं ने एक साथ किया सरेंडर

जगदलपुर। माओवादी संगठन को अब तक का सबसे बड़ा और निर्णायक झटका लगा है। पोलित ब्यूरो सदस्य टिप्पिरी थिरुपथी उर्फ देवजी उर्फ कुम्मा दादा ने अपने तीन शीर्ष साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। सभी ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष हथियार डालते हुए मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

देवजी के साथ जिन बड़े माओवादी नेताओं ने आत्मसमर्पण किया, उनमें केंद्रीय समिति सदस्य मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम, स्टेट कमेटी मेंबर बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर, स्टेट कमेटी सदस्य नुने नरसिम्हा रेड्डी उर्फ गंगन्ना उर्फ सन्नू दादा शामिल हैं। यह आत्मसमर्पण कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार दो केंद्रीय स्तर के माओवादी नेताओं ने एक साथ हथियार डाले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, लगातार बढ़ते फोर्स प्रेशर, सघन ऑपरेशनों और संगठन के भीतर कमजोर पड़ते नेटवर्क के चलते यह बड़ा घटनाक्रम सामने आया है।

वहीं इसे नक्सल उन्मूलन की दिशा में सुरक्षा बलों की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है।

हत्या की नीयत से हमला करने वाले तीन गिरफ्तार

जांजगीर चांपा । जिले के ग्राम बनाहिल में शादी समारोह के दौरान डीजे बंद कराने को लेकर हुए विवाद में हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को मुलमुला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना 22 फरवरी की रात को हुई थी।

पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मुलमुला थाना प्रभारी पारस पटेल ने बताया कि पीड़ित राकेश केवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 22 फरवरी की रात उसके दोस्त विकास केवट की बहन की शादी थी। चुलमाटी कार्यक्रम के दौरान डीजे बज रहा था।

इसी दौरान दिलीप केवट गाली-गलौज करते हुए रांपा लेकर पहुंचा। राकेश के विरोध करने पर दिलीप ने उसके सिर पर रांपा से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दुर्गेश केवट और साहिल केवट डंडा लेकर पहुंचे और राकेश के साथ मारपीट करने लगे। घटना की रिपोर्ट पर मुलमुला थाने में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों दिलीप केवट (27 वर्ष), दुर्गेश केवट (26 वर्ष) और साहिल केवट (19 वर्ष) को हिरासत में लिया। ये सभी बनाहिल गांव के निवासी हैं। पूछताछ में उन्होंने रांपा से हमला और डंडे से मारपीट की बात स्वीकार की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 109 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

कंटेनर से 5 करोड़ का गांजा जब्त

कवर्धा। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कबीरधाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्कर कंटेनर में गुप्त चैंबर बनाकर अवैध रूप से गांजा परिवहन कर रहा था। इसकी सूचना पर थाना चिल्फी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ रुपये का गांजा जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नागालैंड पासिंग एक कंटेनर के माध्यम से भारी मात्रा में गांजा ओडिशा से राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती थाना चिल्फी क्षेत्र में घेराबंदी कर संदिग्ध कंटेनर को रोका गया। तलाशी के दौरान वाहन में बनाए गए विशेष गुप्त चैंबर से 30-30 किलो की 30 बोरियों में भरा हुआ गांजा बरामद किया गया।

कुल जब्त मादक पदार्थ का वजन करीब 9 क्विंटल (900 किलोग्राम) बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये आंकी गई है। वहीं तस्करी में प्रयुक्त कंटेनर की कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है, जिसे भी जब्त कर लिया गया है। मौके से पुलिस ने आरोपी आयाज खान (निवासी भरतपुर, राजस्थान) को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी यह खेप ओडिशा से राजस्थान ले जा रहा था।

पुलिस आरोपी से विस्तृत पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है। इस बड़ी कार्रवाई को जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बिलासपुर से पकड़े गए 7 सुपारी किलर्स

■ **पकड़े गए बदमाशों ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने बीजेपी पार्षद पर सुपारी लेकर हमला किया.**

बिलासपुर। संस्कारधानी में सुपारी लेकर वारदात को अंजाम देने वाले 7 बदमाश पकड़े गए हैं। पकड़े गए बदमाश अंतरराज्यी गैंग से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वो कई खतरनाक वारदातों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लग्जरी गाड़ी और 5 लाख 33 हजार की नकदी बरामद की है।

पकड़े गए गिरोह के लोगों के पास से देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और धारदार हथियार बरामद किया गया है। बदमाशों के पास से 6 मोबाइल फोन और तीन लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं। पकड़े गए मोबाइल फोनों की जांच की जा रही है। फोन से किससे किससे बात की गई, किसके किसके फोन आए ये पता लगाया जा रहा है।

दरअसल, कुछ दिन पहले अंतर्राज्यीय गैंग ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते एक कारोबारी की हत्या की साजिश रची थी। 18 दिसंबर 2025 को सब्जी और जमीन के कारोबार से जुड़े भाजपा पार्षद बंधु मौर्य पर सुपारी लेकर हमला करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बदमाशों की योजना असफल रही। पूछताछ में 19 दिसंबर 2025 को होटल कारोबारी निटी समोसा वाला से हथियारबंद लूट के असफल प्रयास का भी खुलासा हुआ। इसके अलावा सदर बाजार क्षेत्र में त्योहार के दौरान एक ज्वेलर्स की दुकान की तिजोरी लूटने की योजना का भी पर्दाफाश हुआ।

इन सभी वारदातों की कड़ियां पुलिस जोड़ ही रही थी, कि पुलिस को खबर मिली की 17 फरवरी को मां महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी के साथ मारपीट कर सोने के आभूषणों से भरे बैग और नगदी लूट ली गई। घटना के बाद पुलिस ने टेक्निकल और लोकल इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पुलिस के माध्यम से जिले के थाना अहरौरा क्षेत्र में घेराबंदी कर 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद लूट का सभी सामान बरामद किया गया। जिसके बाद बिलासपुर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी मीडिया को साझा की।

गिरफ्तार आरोपियों में विनोद उर्फ बिन्नु प्रजापति, करीम खान, विजय लाम्बा, मोनू उर्फ राहुल उर्फ गुडवा, इरफान अली, नारद उर्फ सुमित श्रीवास और राजू सोनकर शामिल हैं। इन सभी पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

जांजगीर चांपा से खैर लकड़ी की तस्करी का खुलासा, पंजाब के होशियारपुर पहुंचाने की थी तैयारी

■ **खैर की लकड़ी कीमती होती है. इसे लाल चंदन के धोखे में बेचा जाता है. खैर की लकड़ी से बंदूक के बट बनाए जाते हैं.**

जांजगीर चांपा। बीते दिनों नवागढ़ थाना इलाके के भादा गांव से लाखों की अवैध खैर लकड़ी को जब्त किया गया था। जब्त की गई लकड़ी एक बंद पड़े राइस मिल में रखी थी। बंद पड़े राइस मिल में जंगल की काटी गई लकड़ियों को स्टोर किया गया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मिल पर छापा मारा। छापे के दौरान मिल से लाखों की कीमती खैर की लकड़ी बरामद की। 17 फरवरी को पड़े छापे के बाद अब जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं।

पकड़े गए ट्रक ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो निर्दोष है। वो जबलपुर का रहने वाला है। उसे ये बताया गया था कि लकड़ी की खेप जांजगीर चांपा से लेकर निकलना है। इस खेप तय समय पर पंजाब के होशियारपुर में डिलीवरी देनी है। जिसने लकड़ी ले जाने की बात ड्राइवर से कही उसने कहा कि लकड़ी का कागज पूरा पक्का है, किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है। हालांकि ड्राइवर के इस बयान की जांच की जा रही है, कि वो सच बोल रहा है या वन विभाग की टीम को बरगला रहा है। जांजगीर चांपा रेंजर एसपी राठिया का कहना है कि जल्द ही पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। खुद डीएफओ भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

हमने खैर लकड़ी की एक बड़ी खेप को 17 तारीख को पकड़ा है। जांच के दौरान कई और खुलासे हुए हैं। हम एक-एक कड़ियों को जोड़कर असली गुनहगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन इसे पंजाब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहा था- हिमांशु डोंगरे,डीएफओ जांजगीर चाम्पा

वन विभाग के अधिकारियो के मुताबिक इस लकड़ी कर प्रयोग राष्ट्र हित में होता है। खैर की लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसमें घुन नहीं लगता और पानी में सड़ता नहीं है। इस लकड़ी से बंदूक के बट बनाए जाते हैं।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिया विशेष जोर

जगदलपुर। कलेक्टर आकाश छिकारा ने सोमवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली।` जिले में आयुष्मान कार्ड, वय वंदन योजना कार्ड के लंबित हितग्राहियों को योजना से जोड़ने हेतु आयोजित विशेष शिविर के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन पंचायतों में अधिक लंबित संख्या है उनमें प्लान कर एक सप्ताह में शत-प्रतिशत कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के प्रकरणों में हितग्राहियों का चिन्हांकित कर गर्भवती महिलाओं उनके स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए उनको संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से जिले में संचालित जन औषधि केंद्र की स्थिति, जीवन दीप समिति की राशि का उपयोग, एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत हाइपर टेंशन - डायबिटीज की जाँच और फॉलोअप लेने के संबंध में चर्चा किए।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ किर्सी वैरिनेन का बस्तर दौरा

जगदलपुर। बस्तर की संस्कृति और यहां की खूबसूरती को निहारने विश्व से सैलानी हर साल पहुंचते हैं। इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक और सीईओ किर्सी वैरिनेन बस्तर पहुंचे। 23 फरवरी से उनका बस्तर दौरा शुरू हुआ। उनका यह दौरा 6 दिवसीय है और यह 23 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा। किर्सी वैरिनेन 23 फरवरी से 28 फरवरी तक बस्तर में रहेंगी। वे ग्राम धूड़मारास और उसके आसपास के क्षेत्रों का दौरा करेंगी। जिला प्रशासन बस्तर और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के समन्वय से आयोजित इस महत्वपूर्ण यात्रा का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इसका मकसद को ऑन-साइट मेंटरशिप और सूक्ष्म योजना कार्य के माध्यम से बस्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। किर्सी विश्व प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात की भव्यता को निहारेंगी और धुड़मारास में आयोजित होने वाली पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेंगी। परंपराओं और बस्तरिया खान-पान का प्रत्यक्ष अनुभव भी करेंगी।

जंगल के बीच देवपुर नेचर कैंप का शुभारंभ

बलौदा बाजार। देवपुर नेचर कैंप का शुभारंभ हो चुका है। नेचर कैंप का शुभारंभ इस बात का संकेत है कि बलौदा बाजार खासकर बारनवापारा ईको टूरिज्म की राह पर बढ़ चला है। पर्यटन विभाग की ओर से यहां पर मड हाउस मॉडल बनाए गए हैं। इन मड हाउस में ठहरने वालों को प्रकृति और ग्रामीण परिवेश का पूरा आनंद मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। बारनवापारा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक रिसेप्शन भवन भी बनाए गए हैं। इन तमाम सुविधाओं और व्यवस्थाओं से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा, बेरोजगारी भी कम होगी। दरअसल, वनमंडल बलौदा बाजार के अंतर्गत वन परिक्षेत्र देवपुर में विकसित ईको-टूरिज्म नेचर कैंप के मड हाउस का सोमवार को औपचारिक लोकार्पण हुआ। यह पहल सिर्फ एक पर्यटन परियोजना नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को साथ लेकर चलने वाला मॉडल है। इस नए कैंप को स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक निर्माण शैली के साथ तैयार किया गया है।

डीएम ने ली समय-सीमा की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित कर जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने निर्देश दिए है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी मंगलवार और बुधवार को अनिवार्य रूप से प्रात: 10 बजे समय पर कार्यालय पहुंचे तथा आधार बेस्ड उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय पर उपस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ई-ऑफिस प्रणाली में नियमित पत्राचार करते हुए इसे व्यवहार में प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। अभी हाल ही में सम्पन्न हुए।

एनआरएलएम और स्वच्छ भारत मिशन पर फोकस

सुकमा। जिला पंचायत में सोमवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति को गति देने हेतु महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विस्तृत समीक्षा की गई। सीईओ श्री मुकुन्द ठाकुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। लंबित स्वीकृतियों को तत्काल पूर्ण करने, सभी स्वीकृत हितग्राहियों को प्रथम किश्त का 100: भुगतान सुनिश्चित करने तथा प्रथम किश्त प्राप्त आवासों को एक सप्ताह के भीतर प्लिंथ स्तर तक जियो-टैगिंग करने के निर्देश दिए गए। द्वितीय किश्त प्राप्त आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने, वर्ष 2016-23 के अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण करने तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के लंबित मकानों पूरा करने का आदेश जारी किया।

भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु रजिस्ट्रेशन 01 अप्रैल तक

सुकमा। भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 01 अप्रैल निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्नीकल, क्लर्क-स्टोर कीपर टेक्नीकल एवं ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती रैली में सम्मिलित होने अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यता 8वीं, 10वीं एवं 12वीं तथा अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जुलाई 2009 के मध्य होना चाहिए। आवेदकों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन वेबसाईट https://joinindianarmy.nic.in में करना अनिवार्य है। भारतीय थल सेना में सिपाही (फर्मा) पदों पर अविवाहित पुरूष आवेदक की आयु 01 जुलाई 2002 से 01 जनवरी 2008 की मध्य होना चाहिए। ऑनलाईन कॉमन एंट्रेस एग्जाम (सीईई) 01 जून 2026 से 10 जून 2026 तक होने की संभावना हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 0771-2965214 में संपर्क कर सकते हैं।

बांध में मिली गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति

■ **सोनहत विकासखंड के सिंघोर गांव में 70 साल पहले गुम हुई स्वर्ण हाथी की मूर्ति टेडिया बांध में मिली है.जिसे लेकर लोगों में कौतूहल है.**

कोरिया। कोरिया जिला के सोनहत विकासखंड अंतर्गत सिंघोर ग्राम पंचायत में श्रद्धा उमड़ पड़ी है। यहां पिछले 70 साल पहले गुम हुई हाथी की मूर्ति तालाब में मिली है। बताया जा रहा है कि टेडिया बांध से देर रात यह मूर्ति निकाली गई। सूचना फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु मूर्ति के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने एहतियातन फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है।ग्रामीणों के अनुसार यह मूर्ति 'बालम राजा' के समय से स्थापित मानी जाती है।

स्थानीय परंपरा में इसे ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। संतोष कुमार सिंह (गंवाटिया) बताते हैं कि उनके पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यह मूर्ति गणेश स्वरूप मानी जाती है। राजा चंडोल देवता का इस मूर्ति में वास माना जाता था। सहायक आरक्षक समय लाल का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें नवरात्र के दौरान इस मूर्ति के बारे में संकेत मिलते रहे। गांव में कई लोग उन्हें लेकर तरह-तरह की बातें करते थे, लेकिन उनका विश्वास बना रहा। उनके अनुसार लगातार खोज और पूजा-अर्चना के बाद आखिरकार तालाब से वही मूर्ति मिलने की बात सामने आई है। हालांकि वे स्वयं भी मानते हैं कि मूर्ति की वास्तविकता और धातु की पुष्टि जांच के बाद ही संभव होगी। घटना की सूचना मिलते ही तहसीलदार सोनहत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और उस पुराने देवस्थल का भी निरीक्षण किया, जहां से मूर्ति के वर्षों पहले गायब होने की बात कही जाती है।प्रथम दृष्टया इसे स्वर्ण (सोने) की मूर्ति बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि वैल्यूएशन और विशेषज्ञ जांच के बाद ही होगी।

बीजापुर उपजेल और कोतवाली पहुंचे मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष

बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गिरधारी नायक ने अपने बीजापुर प्रवास के दौरान उप जेल और कोतवाली थाना का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण का उद्देश्य मानव अधिकारों के संरक्षण, बंदियों के सुधार तथा पुलिस-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक संवेदनशील एवं पारदर्शी बनाना रहा।

उप जेल निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष नायक ने निरुद्ध बंदियों से सीधे संवाद किया और उनके जेल तक पहुंचने के कारणों की जानकारी ली। बातचीत के दौरान यह सामने आया कि अधिकांश बंदी नक्सल गतिविधियों से जुड़े मामलों में निरुद्ध हैं। उन्होंने बंदियों की शैक्षणिक योग्यता, पारिवारिक स्थिति एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया कि बड़ी संख्या में बंदी कम पढ़े-लिखे या पूर्णत: अशिक्षित हैं। नायक ने कहा कि अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई लोग गलत रास्तों पर चले जाते हैं और अपराध या उग्र गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत का भेद सिखाती है। उसे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

उन्होंने बंदियों को शिक्षा अपनाकर आत्ममंथन करने, अपने भविष्य को सुधारने और पुनर्वास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बंदियों ने भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन की ओर लौटने की इच्छा जताई। निरीक्षण के दौरान जेल में उपलब्ध भोजन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली। आवश्यक सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

इसके बाद आयोग के अध्यक्ष कोतवाली थाना बीजापुर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण व्यवस्था, आगंतुकों को मिलने वाली सुविधाओं, दर्ज अपराधों और निराकृत प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की।

संक्षिप्त समाचार

बजट प्रस्तुत करने से पहले वित्त मंत्री चौधरी ने मुख्यमंत्री साय से मुलाकात की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से

मंगलवार को विधानसभा परिसर स्थित उनके कक्ष में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने वित्त मंत्री को आगामी बजट के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को नई दिशा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की जनकल्याणकारी प्राथमिकताओं, सुशासन और समावेशी विकास के संकल्प को यह बजट और अधिक सशक्त आधार प्रदान करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव सहित मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण तथा वित्त सचिव श्री मुकेश बंसल उपस्थित थे।

डॉ. गौरव सिंह ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से मुलाकात की

रायपुर। डॉ गौरव सिंह ने चिकित्सालय में

भर्ती मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आईसीयू में भर्ती कुशालपुर निवासी नंदिता की माता श्रीमती राजनंदिनी ने कलेक्टर को बताया कि नंदिता का उपचार जारी है और उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। डॉ. सिंह दीर्घायु वार्ड में भर्ती मनीष, उनकी माता निर्मला बघेल तथा तुषार और उनकी माता निशा मानिकपुरी से भी मिले। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। अस्पताल परिसर में संचालित योगिता टी स्टॉल में अवैध सामग्री पाए जाने पर कलेक्टर ने दुकान पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही दुकान संचालक को सख्त हिदायत दी कि दोबारा गुटखा पाउच आदि पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा।

राज्यपाल डेका ने निरामय आरोग्य संस्थान को सौंपी एम्बुलेंस की चाबी

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने मंगलवार

को लोकभवन में निरामय आरोग्य संस्थान रायपुर को एम्बुलेंस प्रदान किया। उन्होंने लोकभवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अपने स्वेच्छानुदान मद से एम्बुलेंस की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। इस वाहन का उपयोग निरामय आरोग्य संस्थान में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. पुर्णेन्द्रु सक्सेना सहित संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।

राज्यपाल से अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने भेंट की

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से मंगलवार को यहां लोकभवन में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्र भूषण वर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर अंबिका चंद्रवंशी, श्री मुरली चंद्राकर, श्री जय प्रकाश वर्मा, श्री रवि वर्मा, श्री मिलींद चंद्राकर, श्री रामगोपाल वर्मा उपस्थित थे।

लोहराघाट व्यपवर्तन और फुलवारी जलाशय योजना के कार्यों के लिए 6.75 करोड़ रुपये स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के दो सिंचाई योजना के कार्यों के लिए 06 करोड़ 75 लाख 96 हजार रुपये स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत योजना के कार्यों में विकासखण्ड-तखतपुर अंतर्गत लोहराघाट व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य के जीर्णोद्धार एवं शेष नहर लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 23 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्यों के पूरा हो जाने पर योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 1539 हेक्टेयर में 105 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 62 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सहित कुल 1601 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। जल संसाधन विभाग द्वारा बिलासपुर के विकासखण्ड-तखतपुर के अंतर्गत फुलवारी जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग एवं मरम्मत कार्य के लिए 02 करोड़ 52 लाख 79 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं। योजना के प्रस्तावित कार्य हो जाने पर रूपांकित क्षेत्र में 826 हेक्टेयर में 97 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा 12 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 838 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

कर्मचारियों के लिए कैशलेश चिकित्सा, कर्मचारियों समेत शिक्षक संगठनों में खुशी की लहर, शिक्षक नेता बोले-सरकार...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों व शिक्षकों के हित में फैसला लेते हुए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल की। सरकार के इस निर्णय का छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों, शिक्षकों ने स्वागतेय बताते हुए सरकार का आभार जताया है।

फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से हम मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सरकार ने बजट में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा को शामिल किया। यह निर्णय कर्मचारी वर्ग और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक कदम है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ बजट 2026 में कर्मचारियों को चिंता मुक्त स्वास्थ्य सुविधा हेतु कैशलेश चिकित्सा का लाभ बजट में किया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को धन्यवाद देते है, बजट में कैशलेश चिकित्सा का प्रावधान का स्वागतेय है। शिक्षकों को रमेश चंद्रवंशी ब्रुक्स 2255/2021 एवं अन्य याचिकाओं में हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण रूप से प्रतिपादित संविलियन से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई। दीर्घकालीन सेवाओं को अप्रासंगिक मानकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। मोदी की गारंटी के तहत क्रमोन्नति/समयमान हेतु निर्धारित 10 वर्ष की सेवा को एक बार (वन टाइम रिलैक्सेशन) शिथिल करते हुए 5 वर्ष किये जाने शिक्षकों की उम्मीद पूरी नही हुई है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन ने कहा कि कैशलेश इलाज की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। साथ ही प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना कर पुरानी पेंशन एवं क्रमोन्नत वेतनमान देने का मांग की है। प्रदेश संयुक्त शिक्षक संगठन ने छत्तीसगढ़ सरकार को ऐतिहासिक निर्णय के लिए भी धन्यवाद दिया है।

शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा कि बजट में शासकीय सेवकों के लिए कैशलेश चिकित्सा सुविधा और बजट प्रदान करने की घोषणा का प्रथम दृष्टया स्वागत किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि कैशलेश चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु उसके नियम शर्तो के सार्वजनिक होने पर ही इस पर पूरी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। पेंशन हेतु शिक्षक स्टाफ संवर्ग की पूर्व सेवा की गणना न होना निराशाजनक है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाने का स्वागत करते हैं पर अन्य शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ सुविधाओं व साधनों में पक्षपात न हो इसका भी ध्यान रखा जाना था। इसके पहले भी आत्मानंद स्कूल खोलकर अन्य शासकीय विद्यालय के बच्चे उपेक्षित रखे गए,अपेक्षा है इस बार ऐसा न हो। जर्जर स्कूलों के लिए नवीन विद्यालय भवन का निर्माण का निर्णय सराहनीय है परंतु सरकार को ये सुनिश्चित भी करना चाहिए कि पूर्व की तरह ये बजट भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए।

महिलाओं की बल्ले-बल्ले! साय सरकार ने महिलाओं के लिए खोला पिटारा

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अपने तीसरे बजट में मातृ शक्ति को केंद्र में रखा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं और बेटियों के लिए कई बड़े ऐलान किए। सबसे प्रमुख घोषणा महतारी वंदन योजना को लेकर रही जिसके लिए सरकार ने 8,200 करोड़ का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।

सरकार ने इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है जिसका असर बजट प्रावधानों में साफ नजर आ रहा है।

महतारी वंदन योजना: 70 लाख महिलाओं को सीधा फायदा: वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आर्थिक आजादी का प्रतीक बन गई है।

बजट आवंटन: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड: योजना शुरू होने से अब तक महिलाओं के बैंक खातों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेजी जा चुकी है।

लाभार्थी: प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं हर महीने इस वित्तीय सहायता का लाभ उठा रही हैं।

छत्तीसगढ़ किसान बजट 2026: साय सरकार ने किसानों के लिए खोला खजाना, 5500 करोड़ से खेतों तक पहुंचेगा पानी, जानें किसानों की जेब में सीधा कितना आएगा पैसा ?रानी दुर्गावती योजना: बेटियों के भविष्य की गारंटी: बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार ने रानी दुर्गावती योजना के तहत एक बड़ा वित्तीय कवच तैयार किया है। इस योजना के तहत प्रदेश की बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1.5 लाख (डेढ़ लाख रुपये) की सहायता राशि दी जाएगी। इसका मकसद बालिकाओं की उच्च शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

आंगनबाड़ी और मितानिनों के क्या हैं प्रावधान ?: ग्रामीण स्वास्थ्य और पोषण के ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया गया है:

आंगनबाड़ी केंद्र: सुविधाओं और पोषण कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए 800 करोड़ आवंटित किये गए हैं।

मितानिन कल्याण: स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी कड़ी मितानिनों के लिए 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

महतारी सदन: महिलाओं के सामाजिक जुड़ाव और ट्रेनिंग के लिए प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाए जाएंगे जिसके लिए 75 करोड़ खर्च होंगे।

बजट 2026 और महिला कल्याण: 1. महतारी वंदन योजना की राशि में क्या कोई बढ़ोतरी हुई है?

बजट में फिलहाल योजना के निरंतर संचालन के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राशि में वृद्धि को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

2. रानी दुर्गावती योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

यह योजना प्रदेश की बालिकाओं के लिए है। पात्रता की विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही विभाग द्वारा जारी की जाएगी, जिसमें आय सीमा और अन्य शर्तें स्पष्ट होंगी।

3. महतारी सदन क्या हैं?: ये महिलाओं के लिए सामुदायिक केंद्र होंगे जहां स्व-सहायता समूह अपनी गतिविधियां चला सकेंगे और महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गोबर खाद आपूर्ति पर कांग्रेस विधायकों ने वन मंत्री को घेरा

■ कार्यवाही से बचने का लगाया आरोप, केदार कश्यप ने कहा- रिपोर्ट का इंतजार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने गोबर खाद की आपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रमाणकों में फर्जी हस्ताक्षर का मुद्दा उठाते हुए वन मंत्री केदार कश्यप को घेरा। वन मंत्री के जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद विधायकों ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। अंत में मंत्री ने रिपोर्ट आते ही कार्यवाही के आश्वासन पर मामला शांत हुआ।

विधायक दलेश्वर साहू ने मरवाही वनमंडल अंतर्गत गोबर खाद आपूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रमाणको में फर्जी हस्ताक्षर को जांच का मामला उठाया। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि 6/1/2026 को ही शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के संदर्भ में जांच चल रही है। 3 सदस्यीय समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो भई दोषी होगा उस पर कार्यवाही करेंगे।

इस पर विधायक ने सवाल किया कि कितने फर्जी हस्ताक्षर के बिल को पास किया गया है? मंत्री ने बताया कि जांच चल रही है। रिपोर्ट आते ही कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने इस पर जांच पूर्ण होने की बात कहते हुए जांच के नाम पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आ गई हैय डीएफओ पर कार्यवाही होना तय है। क्या आप कार्यवाही करेंगे?

इस पर सभापति ने दखल देते हुए विधायक से कहा कि आप मंत्री से अलग से मिल कर बात कर लेंगे। वहीं डीएफओ पर कार्यवाही की बात का जवाब मंत्री द्वारा सही तरीके से नहीं देने पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचाया। सभापति ने इसके साथ स्पष्ट किया कि बिना आसंदी के अनुमति के कोई भी कागज पटल पर नहीं रखा जा सकता।

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि समिति जांच कर रही है, रिपोर्ट आते ही इस पर कार्यवाही कर दी जाएगी। विधायक उमेश पटेल ने कहा कि जो भी तथ्य है, उसे सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दे दीजिए। सभापति ने कहा कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती इसकी प्रक्रिया होती है।

चर्चा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि हमारे विधायक कह रखे है कि जांच हो गई है। अधिकारी दोषी पाया गया है। अगर दोषी पाया गए हैं, तो उसे ससपेंड कर दीजिए। हम यही तो कहा रहे हैं। विधायक ने इस पर कहा कि रिपोर्ट आपके पास कब तक आजाएगी यह बता दीजिए। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रिपोर्ट आते ही इस पर कार्यवाही हो जाएगी।

यह संकल्प का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट: चरणदास महंत

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संकल्प थीम पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट पेश होते ही राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह बजट 'गति' का नहीं, बल्कि 'दुर्गति' का बजट है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प का नहीं, भ्रष्टाचार का बजट है। नई-नई योजनाएं भ्रष्टाचार करने के लिए लाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि शब्दों का मायाजाल बुना गया है। इस बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। नौकरी के नाम पर झुनझुना पकड़ा दिया गया है। जो हड़ताल कर रहे हैं, उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है।

अज्ञान और दुर्गति विनाश का बजट: भूपेश बघेल

■ किसानों, महिलाओं और युवाओं को कुछ नहीं मिला

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संकल्प थीम पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट को लेकर विपक्षी दलों के नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर ने कहा कि यह अज्ञान और दुर्गति विनाश का बजट है।

भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। दो घंटे सिर्फ शब्दों का जाल बुना गया। मैं भी पांच साल बजट पेश किया हूं। एक-एक सड़क, चौक-चौराहों के नाम गिनाए जा रहे थे। धान खरीदी के नाम पर धोखा हुआ है। किसान

का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खरीदी कम हुई है। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल खेला गया है। मंत्रियों के बोलने के लिए कुछ नहीं है। मान्य परंपरा के विपरीत जा रहे हैं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे समय की घोषणाओं को बार-बार पढ़ा जा रहा है। रेलवे ट्रैक सिर्फ यहां के खनिज को लूटने के लिए है। कोई स्टॉपेज नहीं होगा। यह सरकार का तीसरा बजट है, लेकिन मोदी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि आज क्या एक लाख बीस हजार में घर बन सकता है? जिसने बनाया है, वह साहूकार के कर्ज में लद गया है।

सदन में भाजपा विधायक ने उठाया सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा मुद्दा

■ परिवहन मंत्री ने कहा- बीते 1 वर्ष में हुई 6898 मौतें, दुर्घटनाओं को रोकने उठाए जा रहे लगातर कदम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। अब दुर्घटना नहीं बल्कि दुर्घटना में मरने और घायल होने वालों की संख्या लोगों को कचोटती है। भाजपा विधायक सुनील सोनी ने लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर सदन में परिवहन मंत्री केदार कश्यप को घेरा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुनील सोनी ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा मुद्दा उठाया। भाजपा विधायक ने पूछा कि बीते 1 वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई है? रोकथाम के लिए क्या मास्टर प्लान है? इस पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि बीते साल में 6898 मौतें हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में यातायात बेहतर किया जा रहा है।

इसके साथ राजधानी में सुगम यातायात के मुद्दे पर घेरा विधायक ने परिवहन मंत्री को घेरा। सुनील सोनी ने पूछा कि राजधानी में कितनी सिटी बसें चल रही हैं? सस्ता परिवहन राजधानीवासियों को क्यों मिल रहा है? इस पर परिवहन मंत्री केदार कश्यप जवाबनहीं दे पाए कहा- जानकारी लेके उपलब्ध कराऊंगा।

सदन में गूंजा अवैध मोबाइल टावरों का मुद्दा, मुख्यमंत्री ने दिया जवाब

छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों का मुद्दा सदन में उठाया। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बिलासपुर जिले में कई जगहों पर अवैध टावर लगाए गए हैं। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लिखित में दे दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किया जाता है, कितने आवेदन किस-किस सेवा प्रदाता कंपनी से मिले हैं। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित 'Right of Way' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। सुशांत शुक्ला ने आगे सवाल किया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितनों को अनुमति की गई? मुख्यमंत्री ने बताया कि 426 आवेदन आए थे, जिनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है। वहीं 246 आवेदन निजी भूमि से संबंधित होने पर संबंधित सेवा प्रदाता को सुचना दी गई है। इसके बाद विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि अवैध टावर पर कब और क्या कार्रवाई होंगी? इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की लिखित में जानकारी देने के बाद जांच की जाएगी।

महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा क्रय हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि एक लाख से बढ़कर हुई डेढ़ लाख

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने महिला निर्माण श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा 17 सितम्बर 2025 को की गई घोषणा के परिपालन में श्रम विभाग के छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को ई-रिक्शा क्रय हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि 1,00,000 से बढ़ाकर 1,50,000 कर दी गई है।

राज्य सरकार के इस फैसले से हजारों महिला श्रमिकों को

स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अनुदान राशि में वृद्धि से वे आसानी से ई-रिक्शा क्रय कर सकेंगी, जिससे उनकी नियमित आय सुनिश्चित होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार का उद्देश्य महिला श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार के स्थायी साधन उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से न केवल महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, बल्कि समाज में उनकी भागीदारी और सशक्त भूमिका भी सुनिश्चित होगी।

विभागीय श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, बी.ओ.सी. मण्डल के अध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह एवं विभागीय सचिव सह श्रमायुक्त श्री हिम शिखर गुप्ता जी के अनुसार, योजना का लाभ मंडल में पंजीकृत पात्र महिला निर्माण श्रमिकों को नियमानुसार विभागीय वेबवाईट shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करने पर अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम निर्माण महिला श्रमिकों को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है।

तात्यापारा से शारदा चौक व भनपुरी चौक में बनेगा फ्लाई ओवर

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए तात्यापारा से शारदा चौक तक फ्लाई ओवर बनाने की घोषणा की। इसके अलावा भनपुरी में भी फ्लाई ओवर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और पुलिस प्रशासन मिलकर काम करेंगे। वित्त मंत्री चौधरी ने सदन को बताया कि रायपुर राजधानी होने के साथ-साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक गतिविधियों का भी केन्द्र बिंदु है, जिसके कारण यहां ट्रैफिक व्यवस्था एक स्वाभाविक चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने रायपुर के लिए राजधानी पैकेज के तहत महत्वपूर्ण सड़कों- मोवा से सेरीखेड़ी 100 करोड़, लाभांडी से सड्डु- 100 करोड़, भनपुरी चौक फ्लाईओवर- 20 करोड़, मोवा से दलदल सिवनी ब्रिज तक सड़क- 8 करोड़, शारदा चौक से तात्यापारा चौक फ्लाईओवर- 10 करोड़, वीआईपी रोड पर श्रीराम मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज- 7 करोड़, अशोका रतन से कोया कचना में वृहद पुल 8 करोड़ को शामिल किया है। साथ ही रायपुर शहर में विद्युत लाईनों को अंडरग्राउंड किये जाने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कार्य करेंगे एवं इसके लिए अतिरिक्त फंड प्रदाय किया जाएगा।

ए.आई. के फायदे हैं लेकिन जोखिम भी

कल्याणी शंकर

भारत ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए एक समझौता साइन किया है, जो अमरीका के नेतृत्व वाला एक ग्रुप है जो जरूरी मिनेरल्स और आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस (ए.आई.) के लिए एक मजबूत आपूर्ति चेन बनाने पर फोकस करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह अलायंस देश की सैमीकंडक्टर इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए जरूरी है। इस बीच, ए.आई. समिट में अमरीकी डैलीगेशन के प्रमुख ने कहा, ''हम ए.आई. के ग्लोबल गवर्नैंस को पूरी तरह से खारिज करते हैं। हमारा मानना है कि ए.आई. को अपनाने से बेहतर भविष्य नहीं मिल सकता अगर यह ब्यूरोक्रेसी और सैंट्रलाइज्ड कंट्रोल के अधीन है।'' समिट भारत में निवेश लाई, अडानी ग्रुप और अंबानी ने 1-1 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा की है और माइक्रोसॉफ्ट ने 50 बिलियन रुपए के निवेश की। इस शिखर सम्मेलन में इमैनुएल मैक्रों, लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा और एंटोनियो गुटारेस जैसे नेताओं सहित 45 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया। एक मजबूत अमरीकी प्रतिनिधिमंडल और माइक्रोसॉफ्ट, आई.बी.एम. और एडोब जैसी कंपनियों के अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बढ़ते महत्व पर जोर देते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनी क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोग, जिनमें ज्यादातर 30 वर्ष से कम आयु के थे, शामिल हुए। प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव शिखर सम्मेलन को लेकर आशावादी हैं। उनका मानना है कि भारत का ए.आई. निवेश 140 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है।जैसे-जैसे ए.आई. स्वास्थ्य सेवा से लेकर मनोरंजन तक दैनिक जीवन में अधिक एकीकृत हो रहा है, नियामक निरीक्षण की आवश्यकता बढ़ रही है। जबकि ए.आई. बढ़ी हुई दक्षता और बेहतर निर्णय लेने जैसे लाभ प्रदान करता है, यह महत्वपूर्ण जोखिम भी पैदा करता है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ए.आई. तकनीक क्या है और दुनिया क्यों चिंतित है? चिंता का कारण है, क्योंकि यह एक दोधारी तलवार है। डर है कि ए.आई. दुनिया पर कब्जा कर लेगा। ए.आई. रोगी देखभाल और संगठनों के संसाधनों के प्रबंधन के तरीके में काफी सुधार कर सकता है। हालांकि, ए.आई. का उपयोग महत्वपूर्ण नैतिक, गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे उठाता है। नौकरियों, क्रैडिट और आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में भी चिंताएं हैं, जहां पक्षपातपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि डाटा को कैसे संभाला जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं। ए.आई. नियम क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हैं। यूरोपीय संघ का प्रस्तावित आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस एक्ट ए.आई. सिस्टम को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह पारदर्शिता और मानव निरीक्षण सहित उच्च जोखिम वाले अनुप्रयोगों के लिए सख्त आवश्यकताएं लागू करता है। इसके विपरीत, अमरीका में एक खंडित दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्तिगत राज्य अपने स्वयं के नियम बना रहे हैं। ये अंतर एक अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करते हैं, क्योंकि ए.आई. में सार्वभौमिक रूप से अपनाए गए मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। दिल्ली ने एक महत्वाकांक्षी, फुल-स्टैक आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस रोडमैप का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक प्रौद्योगिकी के अगले चरण में एक आत्मविश्वासी नेता के रूप में स्थापित करना है। इंडिया ए.आई. मिशन ने आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए 10,372 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

मुफ्त रेवड़ी संस्कृति जीवंत लोकतंत्र के लिये घातक

ललित गर्ग

भारतीय लोकतंत्र की विडंबना यह है कि चुनाव आते ही जनसेवा का स्वरूप बदलकर जनलुभावन राजनीति में परिवर्तित हो जाता है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त की योजनाओं को चुनावी सफलता का शॉर्टकट बना लिया है। मतदाताओं को तात्कालिक आर्थिक लाभ देकर वोट हासिल करने की प्रवृत्ति लगातार मजबूत हो रही है। आगामी तीन-चार माह में विधानसभा चुनाव होने है, इसी संदर्भ में जब असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुईं, तब इस संस्कृति का प्रभाव और स्पष्ट दिखाई देने लगा। इसी पृष्ठभूमि में देश की शीर्ष अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ने मुफ्त की योजनाओं के अनियंत्रित विस्तार पर गंभीर टिप्पणी की। यह टिप्पणी केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को लेकर एक चेतावनी है।

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य जनकल्याण है। राज्य का दायित्व है कि वह गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को सहारा दे। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी-ये सब कल्याणकारी राज्य की पहचान हैं। लेकिन जब जनहित और चुनावी लाभ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समस्या जन्म लेती है। लक्षित समर्थन और अतिरेक उदारता में अंतर है। एक ओर ऐसी योजनाएं हैं जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती हैं, दूसरी ओर ऐसी घोषणाएं हैं जो केवल मतदाता को तात्कालिक राहत देकर उसे निर्भरता की आदत सिखाती हैं। जब राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य मुफ्त बिजली, मुफ्त यात्रा या नकद वितरण की घोषणाएं करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि यह संसाधन कहां से आएंगे और इसकी कीमत कौन चुकाएगा? राजकोषीय अनुशासन किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का आधार है। यदि राज्य अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए खजाने को खाली करता है, तो दीर्घकालिक विकास प्रभावित होता है। जो धन बुनियादी ढांचे के निर्माण, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण, विद्यालयों की गुणवत्ता सुधार और रोजगार सृजन में लगना चाहिए, वह वोटों की फसल काटने में खर्च हो जाता है। यह प्रवृत्ति केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी चिंताजनक है। लोकतंत्र में मतदाता

की स्वतंत्रता सर्वोपरि मानी जाती है। यदि मतदाता को परोक्ष रूप से आर्थिक प्रलोभन देकर प्रभावित किया जाता है, तो यह स्वतंत्र निर्णय की भावना को कमजोर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने तार्किक प्रश्न उठाया कि राज्य रोजगार सृजन और कौशल विकास पर अधिक ध्यान क्यों नहीं देते? वास्तव में रोजगार ही स्थायी सशक्तीकरण का माध्यम है। जब व्यक्ति अपने श्रम और कौशल से आय अर्जित करता है, तब उसमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों विकसित होते हैं। इसके विपरीत, निरंतर मुफ्त सुविधाएं व्यक्ति को निर्भर बनाती हैं। धीरे-धीरे परिश्रम की संस्कृति कमजोर पड़ती है और समाज में अकर्मण्यता की मानसिकता पनपने लगती है। यह स्थिति लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए खतरनाक है, क्योंकि लोकतंत्र केवल वोट डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सक्रिय और जिम्मेदार नागरिकता का नाम है। चुनाव पूर्व घोषित योजनाओं की निष्पक्षता भी प्रश्नों के घेरे में है। जब आचार संहिता लागू रहने के दौरान बड़े पैमाने पर आर्थिक वितरण होता है, तो विपक्षी दल इसे असमान प्रतिस्पर्धा मानते हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष निगरानी की जिम्मेदारी भारत का निर्वाचन आयोग पर आती है। निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दल मतदाताओं को अप्रत्यक्ष रिश्वत देकर चुनावी लाभ न ले। आचार संहिता का उल्लंघन केवल तकनीकी त्रुटि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का हनन है। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति और गहरी जड़ें जमा सकती है। निस्संदेह, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि राज्यों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की खास तौर से देखभाल करें। हालांकि, जब राजस्व घाटे वाले राज्य मुफ्त की योजनाओं पर बड़ी रकम खर्च करते हैं, तो सरकारी खजाने पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। विडंबना यह है कि जिस धनराशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम बनाने और शिक्षा की सुविधा को समृद्ध करने के लिये किया जाना चाहिए, वो राशि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिये खर्च कर दी जाती है। जरूरत इस बात की है कि कौशल विकास के जरिये लोगों को इस तरह सक्षम बनाया जाए जिससे उन्हें दीर्घकालिक व स्थायी लाभ मिल सकें।

यह भी समझना होगा कि मुफ्त योजनाओं का हर स्वरूप गलत नहीं है। आपातकालीन परिस्थितियों में राहत देना, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय सहायता पहुंचाना, सामाजिक न्याय के तहत वंचित वर्गों को अवसर देना-ये सब राज्य की जिम्मेदारी है। परंतु चुनावी मौसम में अचानक घोषणाओं की बाढ़ आ जाना और दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों की अनदेखी करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत नहीं है। यह राजनीतिक दलों के वैचारिक दिवालियेपन को दर्शाता है, जहां दूरदृष्टि की जगह तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। लोकतंत्र की मजबूती केवल संस्थाओं से नहीं, बल्कि नागरिकों की सजगता से भी आती है। यदि मतदाता केवल तात्कालिक लाभ देखकर मतदान करता है, तो वह अनजाने में ऐसी संस्कृति को प्रोत्साहित करता है जो अंतत: उसी के भविष्य को प्रभावित करती है। परिपक्व मतदाता वही है जो घोषणाओं के पीछे की मंशा और आर्थिक व्यवहार्यता को समझे। वह यह पूछे कि पांच साल बाद राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, विकास की दिशा क्या होगी और रोजगार के अवसर कितने बढ़ेंगे। लोकतंत्र में वोट केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है।

आज भारत स्वयं को वैश्विक मंच पर एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। हम विश्वगुरु बनने का संकल्प लेते हैं, लेकिन यदि हमारी राजनीति लोकलुभावनवाद के जाल में उलझी रहेगी, तो यह संकल्प खोखला सिद्ध होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव तभी सार्थक है जब हमारी नीतियां दूरदर्शी, संतुलित और टिकाऊ हों। मुफ्त की संस्कृति से बाहर निकलकर उत्पादकता, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। यह समय आत्ममंथन का है। राजनीतिक दलों को समझना होगा कि जनता को सशक्त बनाना केवल धन बांटने से संभव नहीं है। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-ये चार स्तंभ किसी भी राष्ट्र की मजबूती तय करते हैं। यदि इन पर निवेश बढ़ेगा, तो नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और राज्य पर बोझ कम होगा। वहीं, नागरिकों को भी यह ठानना होगा कि वे तात्कालिक प्रलोभनों के बजाय दीर्घकालिक विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकतंत्र की सुदृढ़ता तभी सुनिश्चित होगी जब शासन और जनता दोनों अपने-अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें।

निस्संदेह, चुनावी निष्पक्षता के लिये यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव से पहले घोषित की गई या लागू की गई लोकलुभावनी नीतियों व योजनाओं की गहन पड़ताल की जाए। विपक्षी दलों द्वारा बिहार सरकार पर आरोप लगाया गया था कि पिछले साल अक्तूबर में आचार संहिता लागू रहने के दौरान मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 15,600 करोड़ रुपये दिए गए थे। जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध कदम था। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को अपरोक्ष रूप से रिश्वत देने के प्रयासों पर पैनी नजर रखी जाए। साथ ही इस दिशा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्विवाद रूप से चुनाव प्रक्रिया में कोई भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना हमारे जीवंत लोकतंत्र के लिये हानिकारक है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की प्रवृत्ति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करती है। यह कार्य करने की मानसिकता को बाधित करती है और समाज में सरकार-निर्भरता एवं अकर्मण्यता की संस्कृति को जन्म देती है। यदि इस प्रवृत्ति पर समय रहते नियंत्रण नहीं लगाया गया, तो आर्थिक असंतुलन और राजनीतिक अविश्वास दोनों बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यक है कि नीतियों की पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और चुनावी निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यही लोकतंत्र की वास्तविक रक्षा है, यही राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(क) यद् रुद्रश्चन्द्रमास्तेन।
(कोषीतकी 6।7)
(ख) (प्रजापतिः) तं (रुद्रं) अब्रवीन्महादेवोऽसीति। तद्यदस्य तन्नामाकरोच्चन्द्रमास्तरूपमभवत् ।।
(शतपथ 6 ।1 ।3 ।16)
(ग) आग्नेयी पृथिवी ।
(ताण्ड्य 15।4।8)
(घ) इयं (पृथिवी) वै देव्यदितिविश्वरूपी ।
(तैत्तिरीय 1 ।7।6।7)
(ङ) सा (पृथिवी) अग्नि गर्ने विभर्तु ।
(शतपथ 65 ।1 ।11)

अर्थात् (क) जिस कारण से वह रुद्र चन्द्रमा [कहा जाता] है। (ख) प्रजापति ने इस रुद्र को कहा कि तू महादेव है क्योंकि उसका महादेव= महान्दीप्तिवाला नाम रखा, सो वही (रूपसम्पन्न) चन्द्रमा बन गया। (ग) यह पृथिवी आग्नेयी अग्निवाष्पमयी थी। (घ) यह पृथिवी ही विश्वरूपी (= विश्व विमोहक रूप सम्पन्न) अखण्डनीय देवी है। (ङ) उस पृथिवी ने अग्नि को गर्भ में धारण किया ।

इत्यादि अनेक प्रमाणों द्वारा शिव रुद्र भगवान् का चन्द्रमा होता, और पृथिवी का आरम्भ में आग्नेय वाष्पमय होना सुस्पष्ट है तथा इन्हीं पदार्थों के विशेष योगायोग से सुवर्ण आदि धातुओं का बनना भी विज्ञानसिद्ध है जैसा कि हम पूर्व लिख चुके हैं। यही इसका वास्तविक भाव है।

स्थानान्तर में यही कथा आध्यात्मिक किवा आधिदैविक अर्थों के प्राधान्य से भी व्याख्यात की जा सकती है। सो यहाँ मायारहित विशुद्ध ब्रह्म को विष्णु और उसकी अनन्य छाया माया को मोहिनी तथा माया संवलित ब्रह्म (ईश्वर) को शिव समझना चाहिए एवं ईश्वर के वीर्य (सत्ताभाव) से धातुओं (चराचर के धारण शील पञ्चमहाभूतों) की उत्पत्ति माननी चाहिए।

क्रमशः ...

बलराज मधोक

दीवान सुशील पुरी

मधोक जी संघ परिवार के एक मात्र ऐसे लीडर थे ,जिनको पूरी कश्मीर की जानकारी थी। मधोक जी का जन्म 25 फरवरी 1920 को स्कर्दू नगर में हुआ। उनका बचपन स्कर्दू , लेह तथा कश्मीर घाटी के श्रीनगर और बारामुला में बीता।

अक्टूबर, 1947 में कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। महाराजा हरि सिंह जी ने इस संकट की घड़ी में श्रीनगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मधोक को सौंपी थी , क्योकि मधोक उस समय राज्य के संघ प्रमुख थे। उन्होंने भारतीय सेना के आने तक संघ के लगभग 200 स्वयंसेवकों को महाराजा की मदद राइफल प्रशिक्षण देकर श्रीनगर की सुरक्षा का दायित्व बखूबी निभाया था। जब शेख अब्दुल्ला को मधोक की गतिविधियों की

जानकारी मिली तो उसने ना केवल उन्हें अपितु उनके समस्त परिवार को भी राज्य से निष्कासित कर दिया। मधोक का कार्यक्षेत्र दिल्ली और संपूर्ण भारत बन गया।

21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की घोषणा की गई डॉक्टर मुखर्जी को संस्थापक व अध्यक्ष मधोक को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 1952 के आम चुनाव में जनसंघ के 80 उम्मीदवार खड़े किए जिसमें कुल 3 विजय हुए। उनमें से एक डॉक्टर मुखर्जी, दूसरे उनके बंगाल के साथी बंधोपाध्याय एवं तीसरे उमा शंकर त्रिवेदी थे। मधोक जी 1965 से 1967 तक जन संघ के अध्यक्ष रहे। 1967 के आम चुनाव से पहले क्षेत्रीय दलों से गठजोड़ कर लोकसभा में 100 सीटें जीती। मधोक सांसद के रूप में 1960 में नई दिल्ली और 1967 में दक्षिणी दिल्ली से निर्वाचित हुए।

मधोक को अंग्रेजी और हिंदी में काफी कमांड था, अपनी भाषण शैली की वजह से संसद में छा गए थे। पूर्व राष्ट्रपति डॉ नीलम संजीव रेड्डी(जब लोकसभा में स्पीकर थे) ने कहा कि मधोक अकेले ही 350 सांसद सदस्यों पर भारी है। सरकार द्वारा गोवा, दमन-दीव के प्रश्न पर कायरता दिखाने पर मधोक ने जवाहर लाल नेहरू जी को ललकार कर कहा था कि आप भारत के प्रधानमंत्री रहने योग्य नहीं। आप अपने विचारों को तिलांजलि दे दीजिये या कुर्सी को।

1967 में लोकसभा में श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं काशी विश्वनाथ मंदिर पर मुस्लिम शासकों द्वारा वास्तविक रूप नष्ट कर इनके ऊपर व समीप मस्जिदें खड़ी कर ऐसा प्रश्न किया था, जिसका कांग्रेस मंत्री संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए थे। उपर्युक्त जगहों पर मधोक के साथ मुझे (सुशील पुरी)भी कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीनदयाल जी के निधन के बाद मधोक की राजनीती में उथल-पुथल आ गया था। एक दिन उनको जनसंघ कार्यालय में बुलाया गया कि प्रत्याशियों का चयन करना है, जबकि चुनाव नहीं थे। लोगों ने कहा दीनदयाल के निधन के बाद जनता आपको ही जनसंघ का नेता मानती है। इसलिए आप जनसंघ के सदस्यता से त्यागपत्र दे दें। इस बात पर मधोक ने कहा कि-मैं जनसंघ का संस्थापपक सदस्य हूँ, मैं त्यागपत्र नहीं दूँगा, अगर आपलोग देना चाहते हैं तो दे दें। इस पर सब हक्के-बक्के रह गए।

ट्रम्प का 'बोर्ड ऑफ पीस' और गाजा संकट की नई कूटनीति

कांतिलाल मांडोत

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित 'बोर्ड ऑफ पीस' की पहली बैठक ने वैश्विक राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहल पर गठित इस मंच का उद्देश्य गाजा युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, स्थिरता और दीर्घकालिक शांति की रूपरेखा तैयार करना बताया गया है। इस बैठक में भारत ने ऑब्जर्वर देश के रूप में भाग लिया, जबकि करीब 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा ने इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यह पहल केवल मानवीय सहायता तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि इसके माध्यम से वैश्विक शक्ति-संतुलन और कूटनीतिक नेतृत्व की नई दिशा भी उभरती दिखाई दे रही है।

गाजा में पिछले ढाई वर्षों से जारी युद्ध ने अभूतपूर्व मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लगभग 75 हजार लोगों की मौत हो चुकी है और 1.7 लाख से अधिक घायल हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या आम नागरिकों और बच्चों की है। 19 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और 78 प्रतिशत इमारतें क्षतिग्रस्त बताई जाती हैं। इस पृष्ठभूमि में राहत और पुनर्निर्माण की किसी भी पहल का महत्व स्वत: बढ़ जाता है। ट्रम्प ने बैठक में कहा कि यह राशि युद्ध पर होने वाले खर्च की तुलना में बहुत कम है, और यदि सभी देश मिलकर प्रयास करें तो स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है।

बैठक में 9 सदस्य देशों द्वारा लगभग 7 अरब डॉलर और अमेरिका द्वारा 10 अरब डॉलर देने की घोषणा की गई। ट्रम्प स्वयं इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बगया और ट्रम्प के सलाहकार जारेद कुधनर जैसे नाम शामिल हैं। इस संरचना से स्पष्ट है कि यह मंच केवल सरकारी प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं, बल्कि

राजनीतिक और वित्तीय नेतृत्व को साथ लेकर चलने का प्रयास है।

भारत की भागीदारी विशेष महत्व रखती है। भारत ने अभी पूर्ण सदस्यता को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, परंतु ऑब्जर्वर के रूप में उसकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि वह पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से संतुलन और संवाद पर आधारित रही है। एक ओर उसके इजराइल से मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, तो दूसरी ओर वह फिलिस्तीन के मानवीय अधिकारों का भी समर्थन करता रहा है। ऐसे में इस मंच पर भारत की भागीदारी उसकी बहुपक्षीय कूटनीति का हिस्सा मानी जा सकती है।

बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुप्रिण्टो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावेद मिलाई और हंगरी के प्रधानमंत्री विकटन ओबराय स्वयं उपस्थित रहे। इससे यह संकेत मिलता है कि कई देश इस मंच को गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि जर्मनी, ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे कुछ देशों ने सदस्यता नहीं ली, पर ऑब्जर्वर के रूप में भागीदारी की।

इस बैठक का एक अहम पहलू गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती का प्रस्ताव है। लगभग 12 हजार पुलिसकर्मियों और 20 हजार सैनिकों की जरूरत का अनुमान लगाया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और हमास को निरस्त्र करना बताया गया है। इजराइल की यह प्रमुख मांग रही है कि जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ता, तब तक सेना की वापसी संभव नहीं है। दूसरी ओर हमास का कहना है कि जब तक इजराइली सेना पूरी तरह नहीं हटती, वह हथियार नहीं डालेगा। इस टकराव की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बल की भूमिका निर्णायक हो सकती है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता और स्वीकृति पर अभी प्रश्नचिह्न बना हुआ है।

ट्रम्प ने इस मंच को संयुक्त राष्ट्र की निगरानी करने वाला बताया है। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में क्षमता तो बहुत है, लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। यह बयान वैश्विक कूटनीति में नई बहस को जन्म देता है। क्या यह बोर्ड वास्तव में संयुक्त राष्ट्र का पूरक बनेगा या उसकी भूमिका को चुनौती देगा? यूनाइटेड नेशन और विशेष रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिल की भूमिका पर पहले से ही प्रश्न उठते रहे हैं। यदि यह नया मंच प्रभावी हुआ तो वैश्विक संस्थागत ढांचे में बदलाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

बैठक के दौरान ट्रम्प द्वारा ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम देना भी महत्वपूर्ण है। यह संकेत है कि यह मंच केवल गाजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अरब देशों के बीच जटिल संबंध हैं। यदि यह बोर्ड किसी ठोस समझौते की दिशा में आगे बढ़ता है तो क्षेत्रीय राजनीति में नए संतुलन बन सकते हैं।

फिर भी इस पहल को लेकर शंकाएं भी कम नहीं हैं। फंडिंग, सैनिक तैनाती की समयसीमा, प्रशासनिक ढांचा और स्थानीय स्वीकृति जैसे कई सवाल अनुत्तरित हैं। गाजा के दक्षिणी हिस्से में नए शहर बसाने और पर्यटन परियोजनाओं के प्रस्ताव को भी आलोचनात्मक नजर से देखा जा रहा है। पुनर्निर्माण केवल भौतिक ढांचे तक सीमित नहीं होता; इसके लिए सामाजिक विश्वास, राजनीतिक समाधान और दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

भारत जैसे देशों के लिए यह मंच अवसर और चुनौती दोनों है। अवसर इसलिए कि वह वैश्विक शांति प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है; चुनौती इसलिए कि उसे अपने पारंपरिक संतुलन को बनाए रखते हुए नए शक्ति-संतुलन में खुद को स्थापित करना होगा। भारत की भूमिका भविष्य में इस बात पर निर्भर करेगी कि यह बोर्ड कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता से कार्य करता है।

अंतत: 'बोर्ड ऑफ पीस' की सफलता केवल घोषित धनराशि या सैनिक तैनाती पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि इस पर निर्भर करेगी कि क्या यह वास्तव में स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ पाता है। गाजा का संकट केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिक और मानवीय परीक्षा बन चुका है। यदि यह पहल वास्तविक संवाद, न्याय और पुनर्निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है, तो यह वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय सिद्ध हो सकती है। अन्यथा, यह भी इतिहास के उन प्रयासों में शामिल हो जाएगी जो उम्मीदों के साथ शुरू हुए, पर जटिल राजनीतिक यथार्थ के सामने टिक नहीं सकती।

आज का इतिहास

1952 नार्वे की राजधानी ओस्लो में छठे शीतकालीन ओलंपिक खेलों का समापन हुआ।
1956 20 वीं पार्टी कांग्रेस के व्यक्तित्व के व्यक्तित्व और उसके परिणाम पर अपने भाषण में, सोवियत नेता निकिता ख्रूश्चेव ने अपने पूर्ववर्ती जोसेफ स्टालिन के व्यक्तित्व पंथ और तानाशाही की निंदा की।
1975 सऊदी अरब के तत्कालीन शासक शाह फैसल की उनके ही भतीजे राजकुमार फैसल बिन मुसाद ने हत्या कर दी थी।
1986 पीपुल्स पावर रेवोल्यूशन: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने 20 साल के शासन के बाद देश की यात्रा की।
1992 नागोर्नो-करबाख युद्ध-अर्मेनियाई सशस्त्र बलों ने अज़रबैजान के नागोर्नो-करबाखग्रियन के खोजाली शहर से 613 जातीय अजरबैजान नागरिकों को मार डाला।
1994 इजरायली चिकित्सक बरूच गोल्डस्टीन ने मुस्लिम अरबों पर पैट्रिआर्कस की हेब्रोन की गुफा में मस्जिद में आग लगा दी, जिसमें 29 लोग मारे गए और 125 अन्य घायल हो गए।
1996 इजरायल में दो आत्मघाती बमों से 25 लोगो की मौत हो गयी और 80 घायल, हमास ने हमले की जिम्मेदारी ली।
1998 40 वें ग्रैमी अवार्ड्स में प्रमुख पुरस्कार शॉन कॉल्विन, बॉब डाइलन, सारा मैक्लाक्लन और एल्ला जॉन द्वारा जीते जाते हैं।
2005 रेडियो कनाडा इंटरनेशनल ने इसे 60 वें वर्ष में पूरा किया है और 2005 में अपनी 60 वीं वर्षगांठ मनाई है।
2007 फिल्म द डिपार्टेड को 2007 में अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2008 एच.डी.एफ.सी. व सेंचुरियन बैंक ऑफ़ पंजाब के विलय के लिए शेयर अनुपात को मंजूरी दी गई। फ़िल्म नौ कंट्री फ़ॉर ओल्ड मैन को 80वें आस्कर एकेडमी में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म चुना गया।
2009 बांग्लादेश राइफल्स के सदस्यों ने बांग्लादेश के ढाका स्थित अपने मुख्यालय पिलखाना में उत्पीड़न किया, जिसके परिणामस्वरूप 74 लोग मारे गए।
2011 फियाना फील की अगुवाई वाली सरकार को 1921 में आयरिश राज्य के गठन के बाद से आयरिश सरकार को छोड़ने की सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा।
2012 प्रसिद्ध फिल्म द आर्टिस्ट को आत्मा पुरस्कारों में चार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिन्होंने स्वतंत्र फिल्मों को सम्मानित किया।
2013 रूसियों द्वारा एक कानून बनाया गया है जिसमें स्कूलों और उपमार्गों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है।

ट्रंप ने दिया एलियंस की फाइल्स खोलने का आदेश

अभिनय आकाश

उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है तब दक्षिणी गोलार्ध में रात होती है। उधर लोग स्कूल-दफ्तर जाते हैं तो इधर लोग सोने के लिए आंखें बंद करते हैं। दिन और रात के इस फर्क में कुछ घड़ी सब विश्राम करते हैं। 1980 का दशक अमेरिका में एलियन और यूएफओ वाली कॉनंस्परेसी थ्योरी की धूम मची हुई थी। कुछ कमर्शियल पायलट्स ने नवाडा इलाके में उनके ऊपर उड़ रही किसी चमकीनी तस्करी की फोटो खींच ली थी। दावा किया जा रहा था कि हो ना हो यह यूएफओस हैं। यानी कि एलियन के स्पेसक्राफ्ट। सभी का ध्यान नवाडा के रेगिस्तान के बीचों-बीच मौजूद अमेरिका के एक सीक्रेट बेस की ओर जा रहा था। हर किसी को पता था कि रेगिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह है जहां आम लोगों का जाना मना है। हथियार बन गार्ड्स इसकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन इस जगह का नाम बताना तो दूर अमेरिकी सरकार यह तक नहीं मानती थी कि ऐसी भी कोई जगह एकिस्ट करती है। मई 1989 में एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल के एस टीवी ने यूएफओ द बेस्ट एविडेंस के नाम से शो शुरू कर दिया। जिसमें रॉबर्ट लेज़र नाम का एक बंदा यह दावा करता है कि वो इस सीक्रेट बेस पर काम कर चुका है। उसने यहां एलियंस की बॉडीज और एलियंस के नौ स्पेसक्राफ्ट देखे हैं। रॉबर्ट यह तक दावा करता है कि सीक्रेट बेस पर अमेरिका रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है। यानी एलियन की टेक्नोलॉजी से नए हथियार और नए स्पेसक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं और सबूत के तौर पर तरह-तरह की फोटो सबमिट करता है जो संदेह पैदा करने के लिए काफी होते हैं। खूब हंगामा होता है। अमेरिकी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अमेरिका सारे दावे खारिज कर देता है। अमेरिकी सरकार यह तक नहीं मानती कि नवाड़ा में ऐसी कोई जगह मौजूद भी है। लोगों का आज भी मानना है कि अमेरिका ने यहां एलियंस छिपा रखे हैं। अब एक बार फिर यह जगह चर्चा में है। कारण अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का बयान। एक पॉडकास्ट में ओबामा ने एलियंस की मौजूदगी का दावा कर दिया है। ओबामा ने कहा है एलियंस होते हैं लेकिन एरिया 51 में नहीं रखे गए हैं। ओबामा के बयान के बाद एक बार फिर एरिया 51 विवादों में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिकी रक्षा विभाग को यह आदेश दिया है कि एरिया 51, एलियन और यूएफओ से जुड़े जितने भी सीक्रेट फाइल्स अमेरिका में मौजूद हैं, उसकी पहचान की जाए। उन्हें पब्लिक किया जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिरकार एरिया 51 है क्या? अमेरिका यहां क्या करता है? क्यों इस इलाके को इतना सीक्रेट बनाकर रखा गया है? क्या सचमुच अमेरिका ने यहां एलियंस और यूएफओ छिपा कर रखे हुए हैं? और अब ओबामा के दावे के बाद डोनाल्ड ट्रंप कौन से सीक्रेट फाइल्स पब्लिक करने वाले हैं?

अमेरिका का 7वां सबसे बड़ा स्टेट नवाडा जिसकी पहचान लांस वेगास जैसे शहर है। शानो शौकत की जिंदगी, जहां जुआ भी लीगल है। इस चमक धमक से परे नवाजा स्टेट कुख्यात एरिया 51 के लिए है। जहां अमेरिका एटम बम का टेस्ट करता है। एरिया 51 लास वेगास से महज 134 किलोमीटर दूर है। एरिया 51 कंटीले पेड़ो का बियाबान है। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान और अमेरिका का मिलिट्री बेस। नेवाडा का पता स्पेन ने लगाया था। सबसे पहले न्यू स्पेन नाम से कॉलोनी बनाई गई। 1821 में आजादी के बाद नेवाडा मेक्सिको का हिस्सा बना। अमेरिका और मेक्सिको के युद्ध के बाद से यहां पर यूएस का कब्जा है। अमेरिका यहां सुपर पावर डेडली वेपन तैयार करता है। एरिया 51 से मिले सुपरफाइटर का डंका दुनिया में बजता है।

कॉन्सपिरेसी थ्योरी ये भी है कि इस फैसलिटी में क्रैश हुआ एलियन स्पेस क्राफ्ट है। इंजीनियर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे बनाने में लगे हैं। इस 1950 की रोसवेल दुर्घटना से जोड़ा जाता है। पत्रकार एनी जैकबसन ने अपनी किताब एरिया 51 एन अनसेंसर्ड हिस्ट्री ऑफ अमेरिकाज टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में इससे जुड़े चीजों के बारे में बताया। जैकबसेन ने अपनी किताब में लिखा कि इस इलाके की गोपनीयता एलियन की वजह से नहीं बल्कि गुप्त परमाणु परीक्षण और हथियारों के विकास में इसकी भागीदारी से थी। किताब में उन्होंने लिखा कि सूत्र ने दावा किया कि न्यू मैक्सिको में एक फ्लाइंड डिस्क क्रैश हुआ था। इस फ्लाइंग डिस्क को राइट पैटरसन वायु सेना बेस ले जाया गया। बाद में उस मलबे को 1951 में यहां लाया गया, जिसकी वजह से इस जगह का नाम एरिया 51 पड़ा।

यूएफओ को अक्सर लोग एलियंस के साथ जोड़ते हैं। लेकिन कोई भी ऐसी उड़ने वाली चीज जिसके ठीक ठीक पहचान न हो सके, उसके लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होता है। जब और भी यूएफओ देखे जाने लगे और उसके दावे आएं तो एयरफोर्स ने उसकी जांच शुरू की और उसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक का नाम दिया। बाद के सालों में भी यूएफओ देखे जाने की बात सामने आती रहीं। 1969 में अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया। इस समय तक वो यूएफओ देखे जाने के 12 हजार से ज्यादा दावों की जांच कर चुका था। प्रोजेक्ट ब्लू बुक तो खत्म हुआ लेकिन दक्षिणी नेवाडा में एरिया 51 के आसपास यूएफओ देखे जाने के दावे किए जाते रहे। क्योंकि इस प्रतिबंधित इलाके के आस पास आम लोग नहीं जा सकते। ये 24 घंटे और 365 दिन भारी सुरक्षा में रहती थी। तो इस जगह के बारे में कहानियां चल पड़ी। कहा तो ये भी जाता है यहां रिवर्स इंजिनियरिंग करके एलियंस की टेक्नोलॉजी समझने की कोशिश की जाती है। 80 के दशक में राबर्ट बॉब नाम के एक आदमी ने सामने आते हुए कहा कि वो एरिया 51 में काम करता था। राबर्ट का दावा था कि उनका काम परगृहियों से जुड़ी रिसर्च से जुड़ा था। उसने मीडिया को कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उसके मुताबिक ये एरिया 51 में रखे गए एलियन के ऑटोप्सी की फोटो है। बाद में एरिया 51 में उसके काम करने का दावा झूठा निकला। इसके अलावा टाइम ट्रैवल को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि अमेरिका यहां पर समय में आगे और पीछे जाने की रिसर्च कर रहा है। कुछ कहते हैं कि नील आर्म स्ट्रांग चांद पर कभी उतरे ही नहीं। यहीं एरिया 51 में फोटो खींच कर कहा कि उसका अपोलो 11 मिशन चांद पर उतर गया।

अगस्त 2013 में सूचना के अधिकार के तहत एक जानकारी मांगी गई। इसके जवाब में सीआईए को कुछ डॉक्यूमेंट डिक्लासीफाइड करने पड़े। इसी क्रम में फिर उस जगह के बारे में भी बताया गया। जो ला क्यू एयरक्राफ्ट के निर्माण और टेस्टिंग से जुड़ी हुई थी। ये एरिया 51 जगह थी। जिसका पहली दफा तब ही सार्वजनिक जिक्र हुआ। अमेरिकी खुफिया विभाग सीआईए के अनुसार एरिया 51 में 1955 से सीक्रेट एयरक्रॉफ्ट की टेस्टिंग होती थी। जब से अमेरिकी सेना ने सीआईए के यू 2 जासूसी प्लेन की टेस्टिंग शुरू की थी तब से ही। दरअसल, कोल्ड वॉर के वक्त सोवियत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की खूब जासूसी करते थे। ताकी दोनों को एक दूसरे के अगले कदम की जानकारी हो जाए। अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के दोनों टोही विमानों में बड़ा नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने फिर यू टू विमान को लेकर आए।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा 14 फरवरी 2026 को रिलीज हुए नो लाइ विद ब्रायन टायलर कोहेन पॉडकास्ट में पहुंचे थे। इस दौरान जब एक रैपिड-फायर सेगमेंट में उनसे पूछा गया कि क्या एलियंस असली हैं तो उन्होंने कहा था कि वे असली हैं लेकिन मैंने उन्हें नहीं देखा है और उन्हें एरिया 51 में नहीं रखा गया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने 19 फरवरी को कहा है कि वह पेंटागन और दूसरी एजेंसियों को स्रह्ल,.क्क और एलियन जीवन पर सरकारी फाइलों को डीक्लासिफाई करने और जारी करने का निर्देश दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दिखाई गई ज़बरदस्त दिलचस्पी के आधार पर मैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट और एजेंसियों को एलियन और एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का निर्देश दूंगा। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना (यूएपी) और अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट (यूएफओ) और इन बहुत मुश्किल लेकिन बहुत दिलचस्प और ज़रूरी मामलों से जुड़ी कोई भी और सभी दूसरी जानकारी से जुड़ी सरकारी फाइलों की पहचान करने और उन्हें रिलीज करने का प्रोसेस शुरू करने का निर्देश दूंगा। गॉड ब्लेस अमेरिका!

सुंदर पिचाई की सकारात्मक टिप्पणी भावनाओं का सबूत

लव गौर

दिग्गज डिजिटल कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में चल रहे एआई शिखर सम्मेलन में अगर एआई के क्षेत्र में भारत की मौजूदा स्थिति को अद्वितीय बताया, तो उसकी मुख्य वजह है- उपयोगकर्ताओं की बड़ी आबादी, नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रतिभाओं का विशाल पुल और नियम आधारित वैश्विक एआई शासन में भारत का दमदार हस्तक्षेप। बृहस्पतिवार को इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से डरता नहीं है, बल्कि उसने इसमें अपना भविष्य देखा है।

एआई के सुरक्षित, जिम्मेदार और सहयोगात्मक उपयोग के लिए वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस सम्मेलन में पिचाई ने विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर की लागत से एआई हब बनाने की गूगल की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो देश में गीगावाट क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधा और अंतरराष्ट्रीय सब-सी केबल गेटवे के विकास में महत्वपूर्ण है। भारत-अमेरिका कनेक्ट के तहत घोषित सब-सी केबल गेटवे के विकास से दो महाद्वीपों के बीच संचार संपर्क को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इंटरनेट ट्रैफिक सुचारु होगा।

इसके अलावा, गूगल द्वारा छात्रों एवं युवा पेशेवरों के लिए एआई से संबंधित पेशेवर सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने से कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। पिचाई का यह कहना समझा जा सकता है कि भारत में एआई सदियों पुरानी कमियों को दूर करने और नए अवसर पैदा करने का मौका देता है, क्योंकि यहां उद्यमिता का परिवेश तेजी से विकसित हो रहा है और कई स्वदेशी कंपनियां तेजी से विकास कर रही हैं।

भारतीय उद्यमिता परिवेश के बारे में सुंदर पिचाई की सकारात्मक टिप्पणी दिग्गज तकनीकी कंपनियों की भावनाओं को दर्शाती है, जो भारत की क्षमता पर भरोसा करती हैं और यहां निवेश की खातिर उत्साहित भी हैं। वास्तव में, कंपनियों के इस उत्साह के पीछे सरकार की नीतिगत पहल का भी हाथ है, जिसके चलते न केवल भारत में व्यापार सुगमता बढ़ी है, बल्कि नियामक स्थिरता ने भी निवेशकों को आश्वस्त किया है। पर जैसा कि कई तकनीकी दिग्गजों ने रेखांकित किया, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में प्रमुख दावेदारी करने के लिए भारत को अपने मौजूदा 1.2 अरब डॉलर के निवेश को बढ़ाना होगा। अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाने से आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान करने के अवसर तो मिलेंगे ही, रोजगार की नई संभावनाएं भी पैदा होंगी।

मोदी-लूला की दोस्ती ने किया कमाल

नीरज कुमार दुबे

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज वह तस्वीर दिखी जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा में नया संकेत दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इस्पात आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह आपूर्ति शृंखला की मजबूती, सामरिक स्वावलंबन और आर्थिक शक्ति के नए युग की घोषणा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ समझौता मजबूत और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के बीच भरोसे और रणनीतिक तालमेल का प्रमाण है। उन्होंने अगले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डॉलर से आगे ले जाने का लक्ष्य दोहराया। ब्राजील पहले ही लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अब यह संबंध नई ऊंचाई छूने को तैयार है।

राष्ट्रपति लूला ने भी भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता की खुलकर सराहना की। सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को उन्होंने भविष्य की साझेदारी का आधार बताया। उनके साथ आए मंत्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का बड़ा दल यह संकेत देता है कि यह मित्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक धरातल पर भी मजबूत हो रही है।

हम आपको बता दें कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में ब्राजील के साथ खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और

उन्नत तकनीक पर सहयोग भारत को कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

वहीं, क्रिटिकल मिनरल्स समझौता केवल उद्योग की जरूरत नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता है। विश्व में रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का लगभग एकाधिकार रहा है। भारत लंबे समय से निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ब्राजील के साथ यह साझेदारी उस रणनीति को ठोस आधार देती है। इससे भारत की रक्षा, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष और उच्च तकनीक उद्योगों को स्थायी आपूर्ति मिलेगी।

देखा जाये तो भारत और ब्राजील की यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय नहीं है। यह ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूती देती है। जब दो बड़े लोकतंत्र खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक में हाथ मिलाते हैं तो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का समीकरण बदलता है। पश्चिमी शक्तियों और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के दौर में यह समझौता तीसरे ध्रुव की संभावना को मजबूत करता है।

ऊर्जा क्षेत्र में जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत उड्डयन ईंधन पर सहयोग हरित भविष्य की दिशा में कदम है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और जलवायु अनुकूल कृषि में साझा पहल विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति ब्राजील के लिए लाभकारी होगी, वहीं भारतीय औषधि उद्योग को विशाल बाजार मिलेगा।

वहीं रक्षा क्षेत्र में बढ़ता तालमेल हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में सामरिक संतुलन को प्रभावित करेगा। समुद्री सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और तकनीकी साझेदारी से दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं।

देखा जाये तो भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सिद्ध किया है कि मित्रता केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश होती है। ब्राजील के साथ बढ़ती निकटता इसी सोच का परिणाम है। मोदी की नीति बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और स्वायत्त भूमिका की है। एक ओर पश्चिमी देशों से गहरे संबंध, दूसरी ओर रूस से सामरिक तालमेल और साथ ही वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सघन सहयोग। ब्राजील के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और इस्पात समझौता इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने औद्योगिक और सामरिक भविष्य को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं छोड़ेगा।

इस साझेदारी से भारत को कच्चे माल की सुरक्षा, नई तकनीक, निवेश और बाजार मिलेगा। ब्राजील को भारत की तकनीकी दक्षता, औषधि आपूर्ति, डिजिटल ढांचा और विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ मिलेगा। दोनों देश मिलकर वैश्विक मंचों पर संस्थागत सुधार, आतंकवाद के विरोध और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देंगे। यह समझौता एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत अपने पक्के दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आने वाले वर्षों में यदि यह सहयोग योजनाओं से निकलकर जमीन पर उतरता है तो यह एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच नए शक्ति सेतु का निर्माण करेगा। यही वह दिशा है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रभावशाली और निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

मोदी इजरायल से लेकर आएंगे आयरन बीम लेजर सिस्टम

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत की सुरक्षा ढाल की नींव मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। हम आपको बता दें कि भारत पहले ही स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र के निर्माण में जुटा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2035 तक प्रमुख शहरों और सामरिक प्रतिष्ठानों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से सुरक्षित करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 30 किलोवाट क्षमता की उच्च ऊर्जा लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा प्रणाली एमके टू ए इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब भारत की नजर इजरायल की 100 किलोवाट श्रेणी की आयरन बीम प्रणाली पर है, जो आयरन डोम के साथ मिलकर कम दूरी की रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को कुछ ही क्षणों में ध्वस्त कर सकती है।

आयरन बीम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लागत है। जहां पारंपरिक मिसाइल अवरोधन में भारी खर्च आता है, वहीं लेजर किरण से किया गया एक अवरोधन मात्र कुछ डॉलर के बराबर पड़ता है। ड्रोन झुंड जैसे हमलों के दौर में यह प्रणाली आर्थिक और सामरिक दोनों दृष्टि से क्रांतिकारी साबित हो सकती है।

हम आपको बता दें कि भारत सुदर्शन चक्र के तहत मध्यम और लंबी दूरी की बराक आठ प्रणालियों, एआई आधारित सेंसर और साइबर सुरक्षा तंत्र को एकीकृत कर रहा है। इसी के साथ इजरायल की एरो और डेविड स्लिंग जैसी दूरवर्ती अवरोधन प्रणालियों के तत्वों को भी समझा जा रहा है, ताकि बहुस्तरीय सुरक्षा कवच तैयार हो सके। देखा जाये तो ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य का युद्ध पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। उस दौरान भारत ने रैम्पेज मिसाइल, हारोप और हार्पी जैसे कामिकाजे ड्रोन तथा स्पाइस एक हजार सटीक मार्गदर्शित बमों का उपयोग कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाया था। इन प्रणालियों ने सटीकता, मारक क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन

किया था।

हम आपको यह भी बता दें कि फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में इजरायल ने भारत के साथ 8.6 अरब डालर के रक्षा सौदों पर सहमति जताई है। इनमें राफेल द्वारा निर्मित स्पाइस एक हजार बम, 250 किलोमीटर मारक क्षमता वाली रैम्पेज वायु से भूमि मिसाइल, एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल तथा 300 किलोमीटर रेंज वाली आइस ब्रेकर मिसाइल प्रणाली शामिल है। फ्रांस के बाद इजरायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन चुका है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा वर्ष 2017 के बाद इजरायल की दूसरी यात्रा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि दोनों देशों के बीच आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी जाएगी। कनेस्सेट में मोदी का संबोधन इस बढ़ती निकटता का प्रतीक होगा। पिछले नवंबर में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की इजरायल यात्रा के दौरान उन्नत तकनीकों के संयुक्त विकास और सह उत्पादन पर सहमति बनी थी। अब प्रस्तावित समझौता ज्ञापन इस सहयोग को और संस्थागत रूप देगा। भारत केवल खरीददार की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र खड़ा करना चाहता है।

देखा जाये तो इजरायल के साथ यह गहन सहयोग दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के सामरिक समीकरणों को नया आकार देगा। पहला प्रभाव प्रतिरोधक क्षमता में भारी वृद्धि का होगा। यदि आयरन बीम जैसी लेजर प्रणाली सुदर्शन चक्र का हिस्सा बनती है, तो पाकिस्तान की ड्रोन या रॉकेट आधारित रणनीति लगभग निष्प्रभावी हो सकती है। कम लागत में निरंतर अवरोधन की क्षमता दुश्मन के लिए हमले को आर्थिक रूप से भी अलाभकारी बना देगी।

दूसरा प्रभाव मनोवैज्ञानिक होगा। बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच से लैस भारत के विरुद्ध आक्रामक कदम उठाने से पहले विरोधी को कई बार सोचना पड़ेगा। यह स्पष्ट संदेश होगा कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, बल्कि पहले से तैयार रहता है।

तीसरा प्रभाव क्षेत्रीय गठजोड़ के रूप में दिखेगा। नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित तथाकथित षटकोणीय गठबंधन, जिसमें भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब और अफ्रीकी देश शामिल हो सकते हैं, कट्टर धुरी के मुकाबले संतुलन की नई धुरी बना सकता है। इससे भारत की पश्चिम एशिया में सामरिक उपस्थिति और ऊर्जा सुरक्षा दोनों मजबूत होंगी।

चौथा प्रभाव तकनीकी आत्मनिर्भरता पर पड़ेगा। एआई, क्वांटम और उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग से भारत का रक्षा उद्योग अगली पीढ़ी की युद्ध प्रणालियों में अग्रणी बन सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि यह यात्रा केवल द्विपक्षीय औपचारिकता नहीं, बल्कि भविष्य की युद्धक तैयारी का खाका है। भारत अब रक्षात्मक प्रतिक्रियावादी राष्ट्र की छवि से बाहर निकलकर तकनीकी रूप से सुसज्जित, बहुस्तरीय और आक्रामक प्रतिरोधक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। बहरहाल, यदि आयरन बीम, एरो, डेविड स्लिंग जैसी प्रणालियों के तत्व सुदर्शन चक्र में समाहित होते हैं, तो भारतीय आकाश एक अभेद्य कवच में बदल सकता है।

बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से न्यायिक अधिकारियों को जोड़ने के सुप्रीम फैसले के मायने

कमलेश पांडे

पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जारी है, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाली एंट्रीज (जैसे माता-पिता का नाम मेल न खाना या आयु अंतर असंगत होना आदि की गहन जांच होती है। इसी को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग के बीच उभरे विवाद को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 19-20 फरवरी 2026 को कलकत्ता हाईकोर्ट को वर्तमान और पूर्व न्यायिक अधिकारियों (जिला जज रैंक के) को तैनात करने का निर्देश दिया। ऐसा इसलिए कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी और सहयोग न होने से प्रक्रिया अटक गई थी। लिहाजा इस अप्रत्याशित फैसले के राष्ट्रीय मायने अहम व दूरगामी साबित होंगे, क्योंकि यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में न्यायपालिका को निर्वाचन प्रक्रिया में सीधे शामिल करने का बेजोड़ उदाहरण है, जो राज्य-केंद्र संबंधों में तनाव को उजागर करता है। देखा जाए तो यह अन्य राज्यों (जैसे केरल, तमिलनाडु) में एसआईआर विस्तार पर भी प्रभाव डाल सकता है, जहां समान विवाद हो सकते हैं। खास बात यह कि कोर्ट ने ट्रस्ट डेफिसिट और ब्लेम गेम की आलोचना की, जो संवैधानिक संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर जोर देता है। हालांकि इसको लेकर कुछ सार्वजनिक प्रभाव और चिंताएं दोनों हैं। यह ठीक है कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती से दावों-आपत्तियों का निपटारा तेज होगा, और उनकी निर्णय अदालती आदेश माने जाएंगे। हालांकि, इससे नियमित अदालती कार्य प्रभावित हो सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट को वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्वाचन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप को मजबूत बनाता है, लेकिन राज्य सरकारों पर सहयोग न करने का दबाव बढ़ाता है। यूँ तो इस फैसले से अन्य राज्यों पर सीधा कानूनी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पश्चिम बंगाल की असाधारण परिस्थितियों (ट्रस्ट डेफिसिट और ब्लेम गेम) तक सीमित रखा। लेकिन जहां तक अन्य राज्यों में एसआईआर स्थिति का सवाल है तो केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां एसआईआर पहले ही चल रहा था या विवादास्पद रहा, वहां बंगाल जैसी न्यायिक हस्तक्षेप की कोई तत्काल मांग नहीं दिख रही। वहीं 12 राज्यों (यूपी, बंगाल सहित) में एसआईआर प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ चुकी, फॉर्म वितरण 95% पूरा हो चुका है। जहां तक इस फैसले के संभावित प्रभाव की बात है तो यह फैसला अन्य राज्यों के लिए पूर्वाधार बन सकता है, जहां राज्य-ईसीआई विवाद बढ़े तो न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का विकल्प खुले। चूंकि कोर्ट ने असाधारण कदम उठाने पर जोर दिया, जो पारदर्शिता बढ़ाएगा लेकिन नियमित अदालती कार्य प्रभावित कर सकता है। फिर भी कोर्ट का यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट निर्णय/फैसला राज्य सरकारों को केंद्रीय संस्थाओं से सहयोग बढ़ाने का संदेश देता है, वरना समान निर्देश संभव है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती की संभावना मजबूत दिख रही है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। इसलिए एसआईआर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा पर विचार कर रहा है, क्योंकि प्रक्रिया में हिंसा, बीएलओ धमकियां और विवाद बढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हालात बिगड़ने पर पुलिस तैनाती की बात कही, और ईसीआई के पास राज्य पुलिस न मानने पर सेंट्रल फोर्स लेने का अधिकार है।

अगर आपके हाथ पैरों का भी बढ़ गया है कालापन तो दूर करने के लिये फॉलो करें यह टिप्स

आमतौर पर अंडरआर्म ज्यादातर लोगों के लिए काला होता है। अत्यधिक पसीने के कारण यहां अंधेरा दिखाई देता है। यह कालापन आत्मविश्वास को कम करता है। इस वजह से महिलाओं के लिए स्लीवलेस और कट स्लीव के कपड़े पहनने का सपना अधूरा है। यदि अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए किसी डिओडोरेंट का उपयोग किया जाता है, तो वे त्वचा को और अधिक काला करने का जोखिम उठाते हैं।कोई भी प्राकृतिक उपचार त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जानिए पसीने के कारण त्वचा का कालापन कैसे दूर करें।

संकलो में काले मुद्दे को हल करने का तरीका यहां दिया गया है

इनहाने के तुरंत बाद कपड़े न पहनें। दो से तीन मिनट प्रतीक्षा करें। इस दौरान शरीर को सामान्य तापमान पर आना चाहिए। बैक्टीरिया के संक्रमण आदि के कारण नमी के कारण होने वाले संक्रमण से बचने के लिए शरीर को ठीक से सूखने दें।

इअतिरिक्त बालों से बचने के लिए नियमित रूप से शेविंग करते रहें। ऐसा करने से नमी और गंध नहीं आती है। इससे कालेपन से बचा जा सकता है।

प्रसंस्कृत भोजन, शराब और अन्य चीजों के सेवन से बचें जिससे अत्यधिक पसीना आता है, उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों से बचें।

– शरीर में पसीना कम करने वाले पानी, कैल्शियम, बादाम आदि से भरपूर पानी का अधिक सेवन करना चाहिए।

– मौसम के हिसाब से कपड़े चुनें, यानी गर्मियों में कॉटन, थोड़े ढीले कपड़े जिससे ज्यादा तनाव न हो। संकल्प को ज्यादा पसीना नहीं आता।

रेस्टोरेंट या बाहर का खाना खाने से अब नहीं बढ़ेगा वजन

वीकेंड हो या कोई त्योहार हम में से ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ अक्सर डिनर और लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं. वहीं घर से बाहर रहने वाले स्टूडेंट या नौकरी करने वाले लोग भी ज्यादातर समय खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं. ऐसे में हम जब भी खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो कई लोग सलाह देते हैं कि बाहर का खाना खाने से वजन बढ़ जाएगा और मोटापा कि समस्या घेर लेगी. क्योंकि, बाहर खाए जाने वाले भोजन में घर के बने भोजन की तुलना में ज्यादा कैलोरी और फैट होती है और बाहर खाना अनजाने में वजन बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है.

हालांकि, कुछ रणनीतियां हैं जिनका उपयोग करके आप भोजन योजना का पालन करते हुए भी बाहर खाने का आनंद ले सकते हैं...

न्यूट्रिशनिस्ट अरबी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेस्टोरेंट के कुछ खास फूड आइटम्स आपका वेट कम करने में आपकी मदद कर सकता है.

होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते या ऑर्डर करते समय इन 10 हेल्दी और वेट कम करने वाले फूड आइटम्स का जरूर रखें ध्यान

सुशी- कम कैलोरी, हाई फाइबर का सबसे अच्छा ऑप्शन है. ब्राउन चावल और सब्जी से भरे इस रोल का ऑप्शन जरूर चुनें.

पनीर टिक्का- हाई प्रोटीन, मीडियम कैलोरी के लिए पनीर टिक्का का ऑप्शन बेहतर है. इसे सब्जियों और साबुत अनाज के साथ खाएं.

वेजिटेबल कबाब

लो कैलोरी, हाई फाइबर से भरपूर ग्रिल्ड या रोस्टेड कबाब का विकल्प चुनें.

भूनी हुई सब्जियां और पनीर

हाई प्रोटीन, मीडियम कैलोरी के साथ भूनी हुई सब्जियां और पनीर का ऑप्शन जरूर चुनें, इसके साथ साबत अनाज चुनें और ज्यादा सब्जियां खाएं.

सब्जी दाल सूप

कम कैलोरी, हाई फाइबर से भरपूर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ऑप्शन के लिए चुनें.

खिचड़ी

कम कैलोरी, हाई फाइबर विकल्प के लिए साबुत अनाज, दाल और सब्जियों से बना खिचड़ी

स्टीम्ड वेजिटेबल डम्पलिंग

मीडियम कैलोरी, हाई फाइबर विकल्प के लिए साबुत गेहूं या सब्जी आधारित रैपर चुनें.

होल व्हीट मशरूम रैप

मीडियम कैलोरी, हाई फाइबर विकल्प के लिए अधिक मात्रा में सब्जियां खाएं और कम कैलोरी वाले सॉस का चुनाव करें.

क्विनोआ बाउल विद ग्रिल्ड पनीर

हाई प्रोटीन, मीडियम कैलोरी विकल्प के लिए इसे चुनें. बता दें, क्विनोआ फाइबर प्रदान करता है, जबकि पनीर प्रोटीन प्रदान करता है.

बेसन चीला

मीडियम कैलोरी, हाई प्रोटीन ऑप्शन के लिए बेसन, सब्जियों और मसालों से बनाया गया चीला चुनें.

ऑर्डर करते समय, याद रखें...

रिफाइंड अनाज, की जगह साबुत अनाज चुनें.

अधिक मात्रा में सब्जियां और फलियां खाएं.

ग्रिल्ड, रोस्टेड या स्टीम्ड विकल्प चुनें.

ज्यादा कैलोरी और चीनी वाले सॉस और ड्रेसिंग का सेवन सीमित करें.

खूब पानी पियें और मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें. इन विकल्पों को चुनकर, आप अपने वजन घटाने के लक्ष्य और समग्र कल्याण में सहायता करेंगे.

स्किन के लिए गुणकारी है पत्थरचट्टा, जानें कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं

स्किन के लिए जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए अक्सर हम कई तरह के घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो पत्थरचट्टा की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं कैसे इस्तेमाल करें।

खराब जीवनशैली और गलत खानपान की वजह से है कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए महिलाएं महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर कई महिलाएं पार्लर जाकर मेकअप या स्किन ट्रीटमेंट स्किन को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है, इसमें पत्थरचट्टा भी शामिल है। स्किन से जुड़ी समस्याओं से बचाव या राहत का लिए आप अपने स्किन केयर रुटीन में पत्थरचट्टा भी यूज कर सकते हैं। पत्थरचट्टा की पत्तियां एक्ने से राहत दिलाने में मदद करती है। स्किन की एलर्जी कम होती है।

पत्थरचट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं

पत्थरचट्टा की पत्तियां में फ्लेवोनोइड्स, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स समेत कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यह आपकी स्किन पर एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पैदा करते है, जिससे खुजली जैसी समस्या से राहत मिल सकती है। आइए आपको बताते हैं कैसे इसका प्रयोग करें।

– पत्थरचट्टा की पत्तियों को कुचलकर थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को अपनी स्किन के प्रभावित त्वचा पर 15 मिनट के लिए लगाएं और बाद में गुनगुने पानी से अपना मुंह धो लें। – पत्थरचट्टा की पत्तियों का इस्तेमाल करके आप फेस मास्क के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इन पत्तियों का फेस मास्क बनाने के लिए पहले आप इन्हें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर

अगर आप एक महीने तक चाय पीना पूरी तरह बंद कर दें तो क्या होगा?

चाय आज के समय में लगभग हर किसी के जीवन का हिस्सा है. रोज सुबह बिस्तर से उठते ही चाय की चुस्की के साथ अपना नींद खोलना बहुत से लोगों को बेहद अच्छा लगता है. वहीं, नाश्ते के समय भी ज्यादातर लोग चाय पीते हैं. ऐसे में देखा जाए तो बहुत से लोग दिन में कई बार चाय का सेवन करते हैं. अधिकतर लोगों को चाय की ऐसी लत होती है कि वे दिनभर में 3 से 4 बार इसका सेवन करते है. हालांकि, अधिक मात्रा में चाय के सेवन सेहत के लिए नुकसानदेह होता है .

एक महीने तक चाय न पीने के फायदे

चाय हमारे देश में लगभग 90 प्रतिशत लोगों का पसंदीदा हॉट ड्रिंक है. कुछ लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की इच्छा होती है, तो वहीं कुछ लोग दिन में अनगिनत बार चाय पीते हैं. क्योंकि चाय में निकोटिन जैसा ही तत्व तंबाकू में भी होता है. लोगों को इसकी लत लग जाती है. चाय एक प्रकार की ऊर्जा और ताजगी का भी सोर्स है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो चाय रोजाना पीते हैं उसमें मौजूद चीनी की मात्रा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है?

चाय प्रेमियों के लिए एक महीने तक चाय न पीना वाकई एक बड़ी चुनौती जैसा होगा, लेकिन चाय पीने की इच्छा पर अंकुश लगाने से उनके स्वास्थ्य को अनगिनत फायदे मिल सकते हैं. आमतौर पर हम जो चाय पीते हैं उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है. इससे कैलोरी बढ़ती है. इसके अलावा स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, चाय में ज्यादा चीनी की मात्रा पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है.

एक महीने तक शुगर-फ्री रहने के फायदे

इसलिए अगर आप एक महीने के लिए मीठी चाय पीना बंद कर देते हैं, तो आपका पाचन बेहतर हो जाएगा. इससे वजन भी कम होता है. इतना ही नहीं इससे आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नहीं होंगी. यदि आप एक महीने तक चीनी वाली चाय नहीं पीते हैं तो, आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, चीनी के लिए कम लालसा होगी, आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, दांत की सेहत बेहतर हो जाएगी, और संभावित रूप से स्किन साफ हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा चीनी का सेवन मुंहासे में योगदान कर सकता है. हालांकि, चीनी को पूरी तरह से छोड़ने के पहले कुछ दिनों के दौरान आपको लालसा और थकान जैसे वापसी के लक्षणों का अनुभव हो सकता है.

कई अध्ययनों से पता चला है कि एक महीने तक मीठी चाय से परहेज करने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है. मीठी चाय पीने से त्वचा पर दाने और छाले हो सकते है. इसलिए बेहतर है कि अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए मीठी चाय न पियें. चाय पीने की आदत से बचने से सीने में जलन, चक्कर आना और हृदय गति में उतार-चढ़ाव जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. अगर आपके हाथ कांप रहे हैं तो चाय पीने से समस्या और बढ़ सकती है. इसके अलावा, यदि आप चाय पीना बंद कर दें तो हाई ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाएगा.

चेहरा टैनिंग के कारण दिखता है मुरझाया हुआ तो लगा लें ये 5 डी टैन पेस पैक्स, खिल उठेगी त्वचा

धूप चाहे गर्मियों की हो या सर्दियों की, बहुत ज्यादा देर तक त्वचा के संपर्क में आती है तो टैनिंग की वजह बन जाती है. टैनिंग के कारण ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर दाग-धब्बे पड़ गए हैं या मैल जम गया है. इस टैनिंग को कम करने के लिए घर पर ही कुछ फेस पैक्स बनाकर लगाए जा सकते हैं. ये फेस पैक्स स्किन पर निखार लाने का काम करते हैं. इनसे टैनिंग हल्की होने लगती है और त्वचा को उसकी खोई हुई चमक वापस मिल जाती है. यहां जानिए कौनसे हैं ये फेस पैक्स और किस तरह इन्हें घर पर ही आसानी से बनाकर चेहरे पर लगाया जा सकता है.

टमाटर का फेस पैक

त्वचा की टैनिंग कम करने में टमाटर कमाल का असर दिखाता है. टमाटर से फेस पैक बनाने के लिए टमाटर के पल्प को निकालें और इसमें थोड़ा सा खीरे का रस मिला लें. आप चाहे तो टमाटर को सादा भी चेहरे पर लगा सकते हैं. टमाटर के पल्प को 15 से 20 मिनट त्वचा पर लगाकर रखने के बाद धोकर हटाएं. त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स भी निकलने लगती हैं. टमाटर सन डैमेज को कम करने में मददगार होता है.

दूध और हल्दी

टैनिंग हल्की करने के लिए इस सदियों से चले आ रहे नुस्खे को आजमाकर देखा जा सकता है. एक कटोरी में दही लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें. दही और हल्दी के इस मिश्रण को चेहरे पर रूई की मदद से लगा लें. इसे चेहरे पर लगाकर तकरीबन आधे घंटे रखें और फिर धोकर हटाएं. हफ्ते में 2 बार इस मिश्रण को लगाकर देखा जा सकता है.

बेसन और दही

चेहरे पर बेसन और दही को लगाने पर त्वचा एक्सफोलिएट होती है और चेहरे पर जमी डेड स्किन सेल्ट हटने लगती है. बेसन और दही त्वचा से मैल छुड़ाकर त्वचा को दमकदार बनाता है. कटोरी में 2 चम्मच बेसन लें और इसमें जरूरत के अनुसार दही मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15 से 20 मिनट रखें और फिर हल्के हाथों से मलते हुए छुड़ा लें.

मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा

सनटैन दूर करने में मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा का भी अच्छा असर दिखता है. एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 2 चम्मच एलोवेरा जैल मिलाएं. इस फेस पैक को चेहरे पर 15 मिनट लगाकर रखा जा सकता है. इसे छुड़ाने के बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाना ना भूलें.

मलाई और केसर

मलाई को चेहरे पर सादा या फिर केसर के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है. इससे त्वचा का रूखापन दूर होता है, मैल हटता है और टैनिंग कम होने में असर दिखता है. एक कटोरी में चम्मच भरकर मलाई और 1-2 केसर के छल्ले डालकर मिलाएं. इसे उंगलियों पर लेकर चेहरे पर पर मलें. आपको दिखेगा कि चेहरे पर जमा मैल छूटकर निकलना शुरू हो गया है. मलाई को चेहरे पर मलने के बाद पानी से धोकर छुड़ा लें.

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विदेशी ताकतों के इशारे पर चल रही कांग्रेस : अनुराग

नई दिल्ली। भाजपा के लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश-विरोधी और विदेशी ताकतों के कहने पर काम कर रहे हैं।

ठाकुर का यह बयान हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे के बाद आया है। कुछ दिन पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा था। वहां यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने घुसकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बेरोजगारी, महंगाई और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए थे। इस प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश की छवि खराब कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, राहुल गांधी देश-विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं। वे भारत-विरोधी एजेंडा चलाते हैं और नकारात्मक राजनीति को बढ़ावा देते हैं।

लश्कर के गुर्गों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद का सवाल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने की कथित आतंकी साज़िश में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आठ संदिग्ध गुर्गों की गिरफ्तारी पर रिएक्शन दिया।

आरोपियों को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे जाने के बाद, मीडिया से बात करते हुए, मसूद ने आतंकी जांच की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि किसी को भी फंसाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहले भी लोग बरी होने से पहले 20 से 30 साल जेल में बिता चुके हैं, और पूछा कि कथित तौर पर गलत तरीके से जेल में डालने के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। उन्होंने मीडिया से कहा कि वे किसी को भी आतंकवादी बता सकते हैं और वह व्यक्ति 20 साल बाद सामने आता है। ऐसी चीज़ों के बारे में आप न तो यह कह सकते हैं कि ये गलत हैं और न ही यह कह सकते हैं कि ये 100% सही हैं। वे ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।

एनडीए में राज्यसभा सीट शेयरिंग की हलचल तेज

पटना। बिहार की सियासत में इन दिनों राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीटों को लेकर बिसात बिछनी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने गठबंधन के भीतर सस्पेंस बढ़ा दिया है। जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पर उस वादे की याद दिलाई है, जिसमें उनकी पार्टी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने की बात कही गई थी। मांझी का यह कहना कि 'हम मांग नहीं करेंगे, बल्कि इंतजार करेंगे' राजनीतिक गलियारों में एक मूक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। जैसे-जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, क्या एनडीए नेतृत्व अपने इस पुराने साथी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या छोटे दलों की दावेदारी सीट बंटवारे के समीकरण को उलझा देगी? जीतन राम मांझी का यह कहना कि हम आखिरी तक देखेंगे कि वे देते हैं या नहीं, यह संकेत देता है कि हम (HAM) इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है।

संजय राउत ने मोदी सरकार पर कसा तंज

मुंबई। राष्ट्रपति भवन में सी. राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण होने के बाद, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए गुलामी पर उसके रुख पर सवाल उठाए। राउत ने भारत की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए पूछा कि अगर सरकार गुलामी का विरोध करती है, तो वह अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध क्यों रखती है? उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को चुनौती दी, फ्रांस से राफेल जेट की खरीद की आलोचना की और नई दिल्ली के निर्माण में लुटियंस समेत कई हस्तियों के योगदान को उजागर किया। संजय राउत ने कहा कि अगर आप गुलामी की बात करते हैं, तो आप ट्रंप के गुलाम क्यों बन गए? अगर आपको गुलामी से इतनी नफरत है, तो आपको भारत-अमेरिका व्यापार समझौता रद्द कर देना चाहिए, आपने फ्रांस से राफेल क्यों खरीदा? लुटियंस समेत कई लोगों ने नई दिल्ली के निर्माण में योगदान दिया है।

महाराष्ट्र भाजपा की नई टीम का हुआ एलान

मुंबई। महाराष्ट्र भाजपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने पहली बार बीएमसी कॉर्पोरेटर बने नवनाथ बान को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। नवनाथ बान इससे पहले पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रमुख थे और अब वह केशव उपाध्ये की जगह लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने मंगलवार को एक मीडिया वार्ता में नए पदाधिकारियों के नामों का एलान किया। इसमें मुख्य प्रवक्ता, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और युवा मोर्चा अध्यक्ष जैसे अहम पद शामिल हैं। चव्हाण ने बताया कि कुछ महीने पहले केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन इसके तुरंत बाद आचार संहिता और स्थानीय निकाय चुनाव शुरू हो गए। इसलिए वरिष्ठ नेताओं ने तय किया कि नई नियुक्तियों का एलान चुनाव के बाद ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये फैसले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, वरिष्ठ नेता अमित शाह, बी एल संतोष, शिव प्रकाश, देवेंद्र फडणवीस और राज्य के अन्य बड़े नेताओं से चर्चा के बाद लिए गए हैं।

अमित शाह का मिशन सीमांचल, आज से बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर

घुसपैठ-डेमोग्राफी पर पहली बार होगी हाई लेवल बैठक

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 से 27 फरवरी तक बिहार के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान जनसांख्यिकीय परिवर्तन, घुसपैठ और अवैध धार्मिक निर्माण जैसे मुद्दों पर विशेष जोर देंगे। शीर्ष सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में अपनी तरह की पहली उच्च स्तरीय समीक्षा के रूप में वर्णित इस बैठक में, गृह मंत्री सीमांचल के सात जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) के साथ एक व्यापक बैठक की सीधी निगरानी करेंगे। भारत-नेपाल और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर या उसके निकट स्थित ये जिले सीमा पार आवाजाही और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय से संवेदनशील माने जाते रहे हैं।

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने मीडिया को बताया कि बैठक में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों, अवैध घुसपैठ की घटनाओं और कथित तौर पर बिना अनुमति के निर्मित धार्मिक ढांचों की स्थिति पर जमीनी स्तर की जानकारी की समीक्षा की जाएगी। विचार-विमर्श में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ खुफिया आकलन भी शामिल होने की उम्मीद है। गृह मंत्री द्वारा सुरक्षा संबंधी किसी भी तरह की कमियों को दूर करने के लिए नागरिक प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई पर जोर दिए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, शाह घुसपैठ और अनधिकृत धार्मिक निर्माणों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यह पहली बार है कि केंद्रीय गृह मंत्री बिहार में जिला स्तर पर जनसांख्यिकी और घुसपैठ संबंधी चिंताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इतनी व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह पहल सीमांचल क्षेत्र पर केंद्र के बढ़ते ध्यान का संकेत है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता और जटिल सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण हाल के वर्षों में राजनीतिक और सुरक्षा चर्चाओं में प्रमुखता से रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से निकटता के कारण सीमांचल क्षेत्र सुरक्षा और सामाजिक-राजनीतिक कारणों से प्रशासनिक निगरानी में रहा है। सीमांचल जिला समीक्षा के अलावा, शाह बिहार में व्यापक सुरक्षा परिदृश्य और आंतरिक सुरक्षा ढांचे से संबंधित कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में सीमा प्रबंधन, खुफिया समन्वय, पुलिसिंग रणनीतियों और संगठित अपराध और चरमपंथी तत्वों के खिलाफ तैयारियों जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस दौरे के दौरान गृह मंत्री बिहार की समग्र आंतरिक सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए भी समय निकालेंगे। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ होंगे, जिनमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका शामिल हैं। ये अधिकारी खुफिया आकलन और जमीनी रिपोर्टों के आधार पर सुझाव देंगे। उनकी उपस्थिति समीक्षा प्रक्रिया को दिए जा रहे महत्व और बैठकों के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना को रेखांकित करती है।

शाह भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ एक विशेष बैठक भी करेंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु सीमा सुरक्षा चुनौतियां होंगी, जिनमें निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना और अवैध सीमा पार गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उपाय शामिल हैं। नेपाल के साथ बिहार की लंबी और खुली सीमा को देखते हुए, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच समन्वय को मजबूत करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। सीमांचल क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करता रहा है, जिनमें उच्च जनसंख्या घनत्व, प्रवासन का दबाव और सीमित बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

मोदी के इस्राइल दौरे को लेकर कांग्रेस ने लगाया आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने फिलिस्तीनियों को बेसहारा छोड़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में इस्राइल का दौरा कर रहे हैं, जब गाजा में नागरिकों पर निर्दयतापूर्वक हमले जारी हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार फिलिस्तीन के मुद्दे पर प्रतिबद्धता को लेकर दिखावटी और पाखंडपूर्ण बयान देती है, जबकि हकीकत में उसने उन्हें छोड़ दिया है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में कहा कि वेस्ट बैंक में हजारों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित करने की कार्रवाई तेज हो गई है और इसकी वैश्विक स्तर पर निंदा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गाजा में नागरिकों पर इस्राइली हमले लगातार जारी हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इस्राइल और अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों की योजना बना रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा, इसके बावजूद प्रधानमंत्री बुधवार को इस्राइल जा रहे हैं (जहां मोदानी कनेक्शन भी है) और अपने दोस्त नेतन्याहू को गले लगाने वाले हैं, जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि इस्राइल में विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के संसद में संबोधन का बहिष्कार करने की धमकी दे रहा है। उनका आरोप है कि नेतन्याहू इस्राइल में न्यायपालिका की आजादी को कमजोर कर रहे हैं।

रमेश ने दोहराया कि मोदी सरकार फलस्तीन के मुद्दे पर पाखंडपूर्ण रुख अपनाए हुए है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने फलस्तीनियों को छोड़ दिया है, जबकि भारत उन शुरुआती देशों में शामिल है, जिन्होंने 18 नवंबर 1988 को फलस्तीन को देश की मान्यता दी थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्राइल दौरा वहां की आंतरिक राजनीति में भी उलझ गया है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार

कांग्रेस ने कहा-तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा?

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह यहां एआई इम्पैक्ट समिट में भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों के एक समूह द्वारा कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में संगठन के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही इस मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। चिब को पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब की 7 दिन की हिरासत मांगी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि साजिश रची और प्रदर्शनकारियों को रसद मुहैया कराई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच के लिए 7 दिन की हिरासत आवश्यक है।

कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पूरी तरह से असंवैधानिक है। तानाशाह नरेंद्र मोदी की सनक का नतीजा है। देश के संविधान ने हर नागरिक को विरोध का अधिकार दिया है। नरेंद्र मोदी इस अधिकार को ही छीन लेना चाहते हैं। हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे, उनके लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद - जय कांग्रेस

युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी

राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस की कार्रवाई को तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का संकेत बताया। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस सच्चाई को देश के सामने लाने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य आईवाईसी साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है।

राहुल ने एक्स पर लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी

ऐतिहासिक धरोहर है। यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है। मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने 'कम्प्रोमाइज्ड पीएम' के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज़ उठाई है। अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है। यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि इस सच्चाई को देश के सामने रखने के लिए युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब और भारतीय युवा कांग्रेस के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी और मैं अपने बब्बर शेर साथियों के साथ मज़बूती से खड़े हैं। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है। डरो मत- सच और संविधान हमारे साथ हैं। पिछले सप्ताह एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत मंडपम में हुए विवादास्पद बिना शर्ट वाले विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में चिब को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या आठ हो गई है। विपक्ष के नेता द्वारा विरोध प्रदर्शन का जोरदार बचाव ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने अधिक सतर्कता बरती है। वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गरिमा, अनुशासन और जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसे प्रदर्शन के आयोजन के तरीके की अप्रत्यक्ष आलोचना के रूप में देखा जा रहा है।

खेल
प्रमुख समाचार

साउथ अफ्रीका से हारने के बाद भारत पर बढ़ा दबाव

चेन्नई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की करारी हार के बाद भारतीय टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा है। इसी बीच टीम के चेन्नई पहुंचते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर टीम बस में ओपनर अभिषेक शर्मा से गंभीर और तीखी चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। यह मुकाबला 26 फरवरी को एम चिदंबरम स्टेडियम में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाना है, जो भारत के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है।

सोमवार को टीम के चेन्नई पहुंचने के तुरंत बाद सामने आए इस वीडियो में गंभीर और अभिषेक टीम बस में ड्राइवर के ठीक पीछे बैठकर गहन बातचीत करते नजर आए। दोनों के हाव-भाव से साफ दिख रहा था कि चर्चा काफी गंभीर थी।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ फैंस ने इसे सकारात्मक कोचिंग बताया, तो कुछ ने कैमरों के सामने इस तरह की बातचीत पर सवाल उठाए।

भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन से हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक ने शुरुआत में एक चौका लगाया, लेकिन वह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। मध्यक्रम की विफलता के चलते कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम को बड़ी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों ने टॉप ऑर्डर की नीयत और रणनीति पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट बल्लेबाजी क्रम में बदलाव पर भी विचार कर सकता है। हालांकि अभिषेक शर्मा लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। फिर भी चेपॉक की स्पिन-अनुकूल पिच पर होने वाला मुकाबला भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 1068 अंक गिरा निफ्टी 25424 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में गिरावट का असर मंगलवार (24 फरवरी) को भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला और बेंचमार्क इंडेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुए। बाजार में शुरुआती कारोबार से ही बिकवाली हावी रही। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सपाट रुख के साथ 83,079 अंक पर खुला और खुलते ही 83 हजार के नीचे फिसल गया। कारोबार बढ़ने के साथ बाजार में बिकवाली हावी हो गई। कारोबार के दौरान यह 81,934 अंक लुढ़क गया था। अंत में 1068.74 अंक या 1.28 प्रतिशत की बड़ी गिरावट लेकर 82,225.92 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी सपाट रुख के साथ 25,641 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 25,327 अंक के इंट्रा-डे लो तक चला गया था। अंत में 288.35 अंक या 1.12 फीसदी गिरकर 25,424 पर बंद हुआ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव, चीन-भारत सबसे आगे

नईदिल्ली। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एशिया, खासकर भारत और चीन, अब दुनिया की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन बनकर उभरे हैं। आईएमएफ की जनवरी 2026 की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान चीन का है, जो 26.6% रहा। भारत 17% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। इस तरह दोनों देश मिलकर वैश्विक वृद्धि का 43.6% हिस्सा चला रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका 9.9% योगदान के साथ तीसरे स्थान पर है। अन्य देशों में इंडोनेशिया (3.8%), तुर्की (2.2%), सऊदी अरब (1.7%), वियतनाम (1.6%), नाइजीरिया(1.5%), ब्राजील (1.5%) शामिल हैं। जर्मनी का योगदान सबसे कम, 0.9% रहा। आईएमएफ ने अनुमान जताया है कि 2026 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 3.3% रह सकती है।

भारतीय बाजारों से FIIs लगातार क्यों निकाल रहे पैसा?

नईदिल्ली। भारतीय आईटी सेक्टर हाल में दबाव में आया है और आंकड़े साफ दिखाते हैं कि निवेशकों का नजरिया बदल रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने पिछले एक साल में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजी प्रमुख क्रिस्टोफर वुड ने मंगलवार को बीएसई मंथन समिट में कहा कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली के पीछे दो बड़े कारण थे। पहला, 2024 के आखिर में चीन का शेयर बाजार करीब सात गुना अर्निंग्स के स्तर पर गिर गया। इससे विदेशी निवेशकों ने भारत में हिस्सेदारी कम की और पैसा चीन में लगाया। दूसरा, बिकवाली की दूसरी लहर इसलिए आई क्योंकि कई निवेशकों ने ताइवान और दक्षिण कोरिया जैसे बाजारों में ज्यादा निवेश (ओवरवेट पोजीशन) कर रखा था। इसलिए उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने के लिए भारत से पैसा निकाला।

चीन ने जापान की 20 कंपनियां की बैन

बीजिंग। अमेरिका से शुरू हुए टैरिफ और प्रतिबंधों के माहौल के बीच अब एशिया में एक नया व्यापारिक तनाव उभर आया है। जापान की प्रधानमंत्री के ताइवान को लेकर दिए गए बयान के बाद चीन ने सख्त कदम उठाते हुए 40 जापानी कंपनियों पर कार्रवाई की है। चीन ने 20 कंपनियों को निर्यात नियंत्रण (कंट्रोल) सूची में और 20 अन्य को निगरानी सूची में डाल दिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव का संकेत माना जा रहा है। मामला तब गरमाया जब जापान की प्रधानमंत्री की ताइवान को लेकर की गई पुरानी टिप्पणियों पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। ताइवान एक स्व-शासित द्वीप है, जिस पर चीन अपना दावा करता है। चीन ने आरोप लगाया कि ताइवान मुद्दे पर जापान की टिप्पणी उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है।

भारत के शहर 'अत्यधिक शहरी' लेकिन उत्पादकता में पीछे

अमित कपूर

इस वर्ष आई आर्थिक समीक्षा में देश के शहरी विकास पथ के बारे में असाधारण रूप से यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की गई है कि भारत 'आर्थिक दृष्टि से पहले से ही अत्यधिक शहरी' है। फिर भी यह 'अधूरे वादों' की कहानी है। समीक्षा के अनुसार, यह वादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लोगों और कंपनियों के एकत्रीकरण से होने वाली उत्पादकता वृद्धि से संबंधित है।

अधूरा पहलू यह है कि भारत ने अपने सबसे बड़े शहरों और उसके आसपास जनसंख्या का विशाल स्तर तो हासिल कर लिया है, लेकिन इसे उत्पादकता और जीवन स्तर में आनुपातिक रूप से परिवर्तित नहीं कर पाया है। यह दृष्टिकोण महानगरों को या तो 'विकास के इंजन' या 'शहरी आपदा' बताने वाले घिसे-पिटे वाक्यांशों से परे जाकर बहस में एक अधिक तकनीकी प्रश्न उठाता है: किन परिस्थितियों में शहरों का घनत्व, उत्पादकता में परिवर्तित होता है?

शहरी अर्थशास्त्र में लंबे समय से यह तर्क दिया जाता रहा है कि निकटता से मूल्य उत्पन्न होता है। अनुभव के आधार पर देखें तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शहर के आकार को दोगुना करने से उत्पादकता में 3 से 8 फीसदी की वृद्धि देखी जाती है, और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और संस्थानों के अनुकूल होने पर यह वृद्धि कभी-कभी इससे भी अधिक होती है।

आर्थिक समीक्षा में वैश्विक मेटा-विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा गया है कि भारत में अनुकूल परिस्थितियों में शहर के आकार को दोगुना करने से उत्पादकता में लगभग 12 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जो इस बात को उजागर करता है कि अप्रयुक्त या संभावित लाभ कितने महत्त्वपूर्ण हो

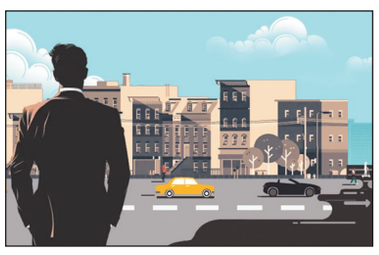

सकते हैं।

सैद्धांतिक रूप से भारत को इन लाभों को हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति में होना चाहिए। इसके सेवा क्षेत्र के समूह वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहते हैं। गुरुग्राम, जो कभी दिल्ली का एक बाहरी हिस्सा हुआ करता था, अब बहुराष्ट्रीय कार्यालयों, वैश्विक क्षमता केंद्रों और फिनटेक फर्मों का एक सघन केंद्र है। यह स्थानीयकरण अर्थव्यवस्थाओं का एक उदाहरण है, जहां कंपनियां साझा प्रतिभा, आपूर्तिकर्ताओं और नेटवर्क प्रभावों का लाभ उठाने के लिए एकत्रित होती हैं। दूसरी ओर यह अनियोजित समूहीकरण की सीमाओं को भी उजागर करता है, जहां ऊंची इमारतें जल निकासी व्यवस्था को चुनौती देती हैं, भीड़भाड़ बढ़ती है और बुनियादी ढांचा पिछड़ जाता है।

भारत के शहरी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 60 फीसदी का योगदान करते हैं और अनुमान है कि 2030 से 2036 तक यह हिस्सा 70 फीसदी के करीब पहुंच जाएगा, जबकि शहरी जनसंख्या लगभग 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी। फिर भी, राजकोषीय सशक्तीकरण इस गति से नहीं हो पाया है।

शहर अपने राजस्व से जीडीपी का 0.6 फीसदी से भी कम हिस्सा जुटा पाते हैं, और संपत्ति कर संग्रह वैश्विक मानकों से काफी कम, लगभग 0.15 फीसदी ही बना हुआ है। यह असंतुलन उत्पादकता बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे में नए सिरे से निवेश को सीमित करता है। समीक्षा में इस बात को रेखांकित किया गया है कि शहर विकास को गति तो देते हैं लेकिन उनमें राजकोषीय स्वायत्तता और समन्वित महानगरीय शासन का अभाव है।

घनत्व के संदर्भ में वेतन-पारिश्रमिक में लचीलापन उन्नत शहरी प्रणालियों की तुलना में कम प्रतीत होता है, जो यह दर्शाता है कि भारत का घनत्व अभी पूरी तरह से 'उत्पादक घनत्व' नहीं है। भीड़भाड़, अनौपचारिकता, खंडित योजना और असमान सेवा वितरण, शहरी समूहों से उच्च वेतन की ओर बढ़ने के सिलसिले को कमजोर करते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि भारत के विशाल आकार के बावजूद, इसके शहर न्यूयॉर्क, लंदन, शांघाई या सिंगापुर जैसे वैश्विक उत्पादन, रसद और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने में क्यों जूझ रहे हैं।

अमित शाह के ऑपरेशन को ओपी चौधरी का बैकअप

रायपुर। 24 फरवरी 20267 दो घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने करीब आधे घंटे का समय बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए किए गए प्रावधान पर दिया। उन्होंने पहले साफ कर दिया कि सरकार आदिवासी इलाकों की विशेष चिंता कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर से नक्सलियों के सफाए के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा तय कर दी है। नक्सली उन्मूलन ऑपरेशन को साय सरकार की योजनाओं का भी तगड़ा बैकअप दे दिया गया है। चौधरी ने जिन योजनाओं की घोषणा की है, उसके जरिए नक्सलियों से निपटने और आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने में खासी मदद मिलेगी। साथ ही नक्सली उन्मूलन के तत्काल अगले वित्तीय वर्ष में बस्तर संभाग के विकास का भी रास्ता खुल जाएगा।वित्त मंत्री ने बस्तर और सरगुजा को बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसे रणनीतिक बजट का नाम भी दिया जा सकता है, जो दूरगामी नतीजे देंगे। अब तक लावलीहुड कॉलेज के लिए पहचाने जा रहे दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से इससे

इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। वहां पर सिर पर गौर मुकुट पहनने वाले आदिवासी युवाओं के गले पर स्टेथिसकोप भी लटका मिलेगा। युवाओं को जोड़ने के लिए सरगुजा के साथ बस्तर में भी ओलंपिक जारी रहेगा और इसके लिए बजट में 22 करोड़ दे दिया गया है। यही नहीं अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके बन जाने से पूरे इलाके में शैक्षणिक माहौल बनेगा और स्थानीय युवाओं की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे।

नक्सलियों से निपटने नई फौज: नक्सलियों के खात्मे के ऐलान के साथ ही बजट में इस बात का ख्याल रखा गया है कि बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ युवाओं की फौज खड़ी होती रहे। इसके लिए 1500 नए फाइटर्स मैदान में उतारे जाएंगे। खास बात यह है कि बस्तर के जंगलों में नेट कनेक्टिविटी को विशेष रूप से बढ़ाया जा रहा है। माना जा रहा है कि संचार के साधन बढ़ने से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा किया जा सकेगा और विकास की गति में तेजी आएगी। बस्तर नेट परियोजना के लिए बजट में पांच करोड़ दिया गया है। सरगुजा के साथ बस्तर विकास प्राधिकरण का बजट 50 करोड़ से बढ़ा कर 75 करोड़ कर दिया गया है।

बस्तर के गांवों का ख्याल

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर के गांवों में पशुपालन का विशेष ध्यान रखा है। ज्ञात हो कि बस्तर में आदिवासियों में पशुपालन की संस्कृति बरकरार है। नक्सलियों के उन्मूलन के बाद अब गांवों में आदिवासी बसाहट सुव्यवस्थित हो रही है और ग्रामीणों में पशुपालन बढ़ता जा रहा है। इसे प्रोत्सहन देने के लिए बजट कें 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नदी बदलेगी तस्वीर

इंद्रावती नदी अब तक आतंक का पर्याय रहा है। समय के साथ वहां जनजीवन सामान्य होता जा रहा है। नक्सली दहशत के कारण अब तक इंद्रावती नदी को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जा सकी थी। अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में इंद्रावती नदी पर मटनार और देउरगांव बैराज के निर्माण की ऐतिहासिक घोषणा की गई है। इसके लिए 2024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे गांवों को जोड़ने के लिए 68 किमी लंबी नहर भी बनाई जाएगी, जिससे फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

बजट प्रतिक्रिया

'विकसित छत्तीसगढ़' का रोडमैपः चेंबर अध्यक्ष थौरानी

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे राज्य की 3 करोड़ जनता, विशेषकर उद्योग एवं व्यापार जगत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया है. उन्होने कहा कि 1.72 लाख करोड़ का यह दूरदर्शी एवं संतुलित बजट संकल्प की भावना के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का सशक्त रोडमैप प्रस्तुत करता है.

प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट का छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्वागत किया है. थौरानी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का अभिनंदन करते हुए कहा कि यह बजट सुशासन, पारदर्शिता, निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास के माध्यम से राज्य को आत्मनिर्भर एवं प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर करेगा. यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत ञ्च2047 के विजन से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ को नई औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है.

अंतिम व्यक्ति के हितों को प्राथमिकता देने वालाः थोरानी

प्रदेश अध्यक्ष सतीश थोरानी ने विशेष रूप से उद्योग एवं व्यापार से संबंधित प्रावधानों का स्वागत करते हुए कहा कि बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स को नया भवन प्रदान करने का निर्णय व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊर्जा देगा. राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु ?250 करोड़ का प्रावधान औद्योगिक निवेश, उत्पादन क्षमता एवं व्यापक रोजगार सृजन को गति देगा. व्यापार और उद्योग को नई ऊर्जा देते हुए बजट में व्यापारिक अधोसंरचना और औद्योगिक विकास के लिए किए गए विशेष प्रावधानों से प्रदेश में निवेश का वातावरण निर्मित होगा. उद्योगों के बजट को 248 करोड़ से बढ़ाकर 775 करोड़ (लगभग 3 गुना वृद्धि) करना सरकार की औद्योगिक विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है.

सतीश थौरानी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र को समान रूप से सशक्त करते हुए छत्तीसगढ़ को निवेश, नवाचार और रोजगार का अग्रणी केंद्र बनाएगा एवं जनविश्वास, जनकल्याण और जनसमृद्धि की त्रिवेणी पर आधारित होकर प्रदेश को समृद्ध, समर्थ और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.

जन-कल्याणकारी और व्यापार-हितैषी

बजट प्रतिक्रिया के अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, कार्यकारी अध्यक्ष जसप्रीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष लोकेश चंद्रकांत जैन, दिलीप इसरानी, मंत्री प्रशांत गुप्ता, सदस्य-प्रसुन दीक्षित,

महिला चेम्बर अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता, कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.

अंतिम व्यक्ति के हित को प्राथमिकता देने वाला- सीए चेतन तारवानी

सीए चेतन तारवानी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट अंतिम व्यक्ति के हित और योजनाओं को प्राथमिकता देने वाला है, लेकिन कर्ज और खर्च में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि भविष्य में कर्ज बढ़ा तो टैक्स बढ़ सकते हैं. उद्योगों पर अप्रत्यक्ष दबाव आ सकता है, लेकिन अभी स्थिति नियंत्रण में दिख रही है क्योंकि अगर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग रहा है तो ठीक है. इसके साथ किसान और कृषक के लिए बीमा योजना का स्वागत करते हुए व्यापारियों के लिए बीमा की वकालत की.

नारी शक्ति को मिलेगी नई उड़ानः भारवि वैष्णव

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बजट में महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं का भारतीय स्त्री शक्ति संगठन ने स्वागत किया है। संगठन की छत्तीसगढ़ प्रांत सचिव भारवि वैष्णव ने 'महतारी सदन' और 'रानी दुर्गावती योजना' को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक 'गेम चेंजर' पहल बताया है. भारवि वैष्णव ने बयान जारी कर कहा कि सरकार की यह नई सोच प्रदेश की महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगी.

एनएचएम कर्मियों ने अनदेखी पर जताया अफसोस

एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरि ने कहा कि यह थीम राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष घोषणा या ठोस पहल नहीं की गई. प्रांतीय प्रवक्ता पुरण दस ने कहा कि बजट में उनके हितों की अनदेखी की गई है. प्रांतीय महासचिव कौशलेस तिवारी ने कहा कि ह॥रू कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ठोस निर्णय सामने आएंगे।

बजट में न्यायधानी के विकास को सरकार ने लगाया पंख

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 24 फरवरी को तीसरा बजट पेश किया। बजट में राज्य के दूसरे महत्वपूर्ण शहर बिलासपुर को महानगरों की तर्ज पर विकसित करने के लिए कई घोषणाएं की गई है। महानगरों की तर्ज पर विकसित हो रहे बिलासपुर में महानगरों की तरह सुविधाएं देखने को मिलेंगी।

बिलासपुर शहर के बीचों-बीच स्थित राजीव गांधी चौक से सीपत चौक तक फ्लाईओवर बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए बजट में स्वीकृत किया गया है। राजीव गांधी चौक से नेहरू चौक तक बनने वाला फ्लाई ओवर तीन दिशाओं में विभाजित होगा। इसे जबलपुर के मदन महल जैसा बनाया जाएगा। वहीं बिलासपुर के मेलनाडीह से मस्तूरी नगर तक सड़क बनाने की स्वीकृति विधायक सुशांत शुक्ला की मांग पर बजट में दी गई है। यह सड़क मेलनाडीह से टेकर-सेलर व्हाया कबारी होते हुए सीपत तक बनेगी। इसके अलावा बिलासपुर के उसलापुर गीता पैलेस से अमेरी अंडर ब्रिज तक चार करोड़ रुपये की सड़क तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की मांग पर स्वीकृत की गई है। बिलासपुर के चकरभाठा बस्ती से धमनी पहुंच मार्ग के लिए विधायक धरमलाल कौशिक की मांग पर दो करोड़ रुपये सड़क हेतु स्वीकृत की गई है।

बिलासपुर के एयरपोर्ट के विकास के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ विजिबिलिटी असिस्टेंस फॉर यात्री उड़ान के लिए बिलासपुर के साथ ही जगदलपुर और अंबिकापुर में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए तीस करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।इसके अलावा बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोनी में कैंसर अस्पताल के लिए 175 पदों पर भर्ती के लिए सेटअप की स्वीकृति दी गई है। सेटअप में एक्सपर्ट डॉक्टर, टेक्निकल पदों के साथ ही रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और क्लर्कल स्टाफ भी है।

विकास, महिला सशक्तीकरण और समावेशी प्रगति का आधारः रमेश सिंह ठाकुर

रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी, जिला रायपुर के जिलाध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर ने इसे राज्य के विकास की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताया है।

जिलाध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। हमारी भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट राज्य के समावेशी विकास को नई गति देगा तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस जनकल्याणकारी बजट का पूर्ण समर्थन करते हैं और इसे प्रदेश की प्रगति का सशक्त आधार मानते हैं।

उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बालिकाओं को 1.50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना शहरी क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई एवं विकास को गति देने के लिए मठनार एवं देउर गांव बैराज निर्माण हेतु 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

संकल्प का नया जुमला बजटः दीपक बैज

रायपुर। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ज्ञान गति की असफलता के बाद संकल्प का नया जुमला वित्त मंत्री ने फेंका है। यह बजट भी जनता को निराश करने वाला बजट है। वित्त मंत्री हाई स्कूल के बच्चे के समान कल्पनाओं में डूबते नज़र आये। इनका बजट राज्य की जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आया। उन्होंने अपने बजट भाषण में बस्तर एवं सरगुजा के विकास के सब्जबाग जो दिखाये, लेकिन इन वादों को पूरा करने बजट प्रावधान निराश करने वाले रहे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले बजट में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की घोषणा वित्त मंत्री ने किया था, इस बजट में वे यह नहीं बताये कि उनमें से कितने की भर्ती हुई? भाजपा ने विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के पांच साल में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में नई नौकरियों के लिए वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया। न नये स्कूल खोलने की बात है, न नये महाविद्यालय खोलने की बात है और न ही कौशल उन्नयन के लिए कुछ है। यही नहीं न नये सिंचाई के बांध बनाने के लिए कुछ है और न ही महिला स्व-सहायता समूहों के रोजगार के लिए कुछ है।

संकल्प कार्पोरेट लूट के आगे नतमस्तक : ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्री के बजट में जो संकल्प है, वह संकल्प कॉर्पोरेट लूट के आगे नतमस्तक होने का ही संकल्प परिलक्षित हो रहा है, जनकल्याणकारी मदो की उपेक्षा करके केवल उद्योग विभाग का बजट ही 3 गुना किया गया है। विगत बजट 165000 करोड़ का था और उसके बाद अनुपूरक बजट 35000 करोड़ अर्थात कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कुल बजट 2025-26 में, इस बजट में मात्र 172000 करोड़ अर्थात लगभग 15 प्रतिशत कटौती की गई है। सिंचाई के लिए मात्र 68 किलोमीटर नहर, विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में सिंचाई का रकबा 2.5 प्रतिशत घटा है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा में मेडिकल कालेज पूर्ववर्ती सरकार के समय के ही है, कुनकुरी मेडिकल कालेज की घोषणा पिछले बजट का है, मेडिकल कॉलेज रायपुर में हॉस्टल का प्रावधान भी पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय का है, यह सरकार केवल योजनाओं को रोकने और झूठा श्रेय लेने का काम कर रही है।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य के बजट में केंद्रीय योजनाओं का श्रेय लिया जा रहा, रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे तो याद है।

बजट महिलाओं को निराशा करने वाला : वंदना राजपूत

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक है। यह बजट काल्पनिक है, धरातल पर बिल्कुल शून्य है। बजट महिलाओं को निराशा किया है। प्रदेश की महिलाओं को इस बजट से यह विश्वास था कि महिला सुरक्षा और महिलाओं के रोजगार पर कुछ विशेष पैकेज रहेगा लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। बजट में महिलाओं को रोजगार देने के लिये कुछ नहीं है। रानी दुर्गावती योजना भी स्पष्ट नहीं है। बस्तर में वनोपज संग्रहण काम में लगी महिलाओं के लिये भी बजट में कुछ नहीं है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रू. में एलपीजी गैस देने का आश्वासन दिया था। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा करने वाले भाजपाई गैस सब्सिडी के लिए एक रुपए का भी बजट प्रावधान नहीं कर पाए हैं। यह बजट सिर्फ लोक लुभावन और कागजों की शोभा बढ़ाने वाली बजट है मध्यमवर्गी एवं गरीब वर्ग परिवार के लिए कुछ भी नहीं। छात्राओं का स्कूल, कालेज बिना शुल्क पहुंचाने का वादा किया था, इस बजट में उस पर भी कुछ नही है।

बिना रोड मैप का दिशाहीन और निराशाजनकः अजय गंगवानी

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने बताया कि आज वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने सांय सरकार का तीसरा बजट पेश किया, इस बजट से छत्तीसगढ़ की आम जनता किसान युवा महिला और आदिवासी, कर्मचारी, व्यापारी और गरीब एक उम्मीद और आस लगाकर बैठे थे कि इस बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, सांय सरकार उनके जेब में सीधे पैसा डालने का काम करेगी. उन्हें उम्मीद थी कि सांय सरकार का यह बजट समृद्धि का बजट होगा, वित्तीय अनुशासन का बजट होगा, जनकल्याणकारी योजनाओं और छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट होगा परंतु यह बजट पूरी तरह जुमलेबाजी और आंकड़ों की बाजीगरी का बजट है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने बताया कि ना इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया, ना 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की मोदी गारंटी को पूरा करने का कोई ईमानदार प्रयास दिखा. छत्तीसगढ़ की माताएं और बहनें इस बार उम्मीद और लगा कर बैठी थी कि 500 में सिलेंडर देने की मोदी गारंटी को पूरा करने की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी करेंगे परंतु वह भी पूरी तरह निराश हुई. मोदी गारंटी में 100 दिन में अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा करने वाली सांय सरकार ने फिर छत्तीसगढ़ के 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को ठगा।

स्वास्थ्य व्यवस्था सहित आदिवासियों की अनदेखीः साहू

रायपुर। इस साल के भाजपा के 'संकल्प' बजट 2026-27 में किसान, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्र के लिए कुछ खास प्राथमिकता सरकार द्वारा नहीं दी गयी है, यह कहना है आम आदमी पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उत्तम जायसवाल का। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान नहीं रखा गया है। महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं दिया गया।रसोइया संघ की मांगों को फिर अनदेखा किया गया।पिछले साल के बजट में पेट्रोल पर वैट कटौती करते हुए पेट्रोल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर कम किया था लेकिन इस साल आम लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। पीएम आवास को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है,जबकि पिछले साल पंचायत राज में 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास के लिए किया गया था लेकिन आज भी लाखों लोगों को पीएम आवास नहीं मिल पाया है।कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवलाल नरेटी ने कहा कि बस्तर और सरगुजा को विकास के नाम पर सिर्फ झुनझुना पकड़ाया गया है।बजट 2026-27 में स्वास्थ्य क्षेत्र 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने,1500 करोड़ आयुष्मान और ह॥रूके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने रखा है जबकि राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है।

रायपुर में इतिहास और पत्रकारिता का अद्भुत संगमः डॉ. लोकेश शरण की क्रांतिकारी धाराएं का विमोचन

रायपुर । भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी अध्यायों को नए सिरे से सामने लाने वाली पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्रांतिकारी धाराएं का विमोचन रायपुर के वृंदावन हॉल, सिविल लाइन में हुआ। श्लोक ध्वनि फाउंडेशन और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त आयोजन में यह समारोह संपन्न हुआ। पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं शोधकर्ता डॉ. लोकेश शरण हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् गायन से हुई जिसने पूरे वातावरण को राष्ट्रीय भाव से भर दिया।

पुस्तक क्यों लिखी- लेखक की जुबानी

डॉ. लोकेश शरण ने बताया कि बचपन से ही क्रांतिकारियों की कहानियों से उनका गहरा लगाव रहा है। शिक्षकों की प्रेरणा और

पत्रकारिता के वर्षों के अनुभव ने इस शोध को आकार दिया। उनके पुत्र ने भी उन्हें इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों का इतिहास अब तक न तो पूरी तरह सामने आया है और न ही सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है। पाठ्यपुस्तकों और मुख्यधारा के इतिहास लेखन में इन धाराओं को जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। यह पुस्तक उसी कमी को दूर करने का प्रयास है।

डॉ. शरण ने छत्तीसगढ़ सहित देश के कई हिस्सों में जाकर मैदानी शोध किया। प्राथमिक स्रोतों, स्थानीय दस्तावेजों और क्षेत्रीय साक्ष्यों के आधार पर तैयार यह पुसस्तक केवल संकलन नहीं बल्कि मौलिक शोधकार्य का परिणाम है।

वंदे मातरम् सबसे बड़ा हथियार था

मुख्य अतिथि डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था यह पूरे देश को जोड़ने वाली शक्ति थी। उन्होंने कहा कि इस संग्राम की जड़ें हमारी मिट्टी में हैं जहाँ अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ी। वंदे मातरम् की शक्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह गीत अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे प्रभावी प्रेरक शक्ति था। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे मातरम् से बड़ी तोप अंग्रेजों के पास नहीं थी।

डॉ. पूर्णेंदु सक्सेना ने कहा कि किसी साधक द्वारा किया गया क्षणिक कार्य भी युगों तक अपना प्रभाव छोड़ता है। क्रांतिकारियों के बलिदान को केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि जीवन का अंग बनाना चाहिए।

विद्वानों ने क्या कहा?

डॉ. वंश गोपाल ने कहा कि डॉ. लोकेश शरण में शोधार्थियों से भी अधिक जिज्ञासा और लगन देखी है। कई स्थानों पर जाकर शोध करना अत्यंत कठिन काम है लेकिन लेखक ने यह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक का नाम और कवर पेज ही पाठक को रोमांचित कर देते हैं।

शशांक शर्मा ने कहा कि लेखक ने विषय की परंपरागत सीमाओं से आगे बढ़कर नया दृष्टिकोण दिया है। उन्होंने विशेष रूप से चौरी-चौरा कांड पर लिखे पाँच पृष्ठों की प्रशंसा की और कहा कि यह प्रसंग इतनी गहराई और तथ्यपरकता से पहले कम ही लिखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्रांतिकारी इतिहास को जानबूझकर अधूरा रखा गया जबकि यह पुस्तक तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने रखती है।

डॉ. ए.डी.एन. वाजपेयी ने कहा कि यह पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई स्थापित अनुमानों को चुनौती देती है। यह इतिहास की अलग-अलग धाराओं को जोड़ने वाला काम है। उन्होंने कहा कि डॉ. लोकेश शरण इस कृति के माध्यम से भारत के महत्वपूर्ण इतिहासकारों में अपना स्थान बनाएंगे।

प्रश्न-उत्तर सत्र

कार्यक्रम में एक विशेष प्रश्न-उत्तर सत्र भी हुआ जिसमें उपस्थित शोधार्थियों, पत्रकारों और साहित्यप्रेमियों ने लेखक से सीधे सवाल किए। डॉ. लोकेश शरण ने शोध के स्रोतों, प्राथमिक सामग्री की प्रमाणिकता और छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन की स्थानीय धाराओं पर विस्तार से उत्तर दिए। इस संवाद ने पुस्तक की वैचारिक गहराई को और स्पष्ट किया।

कार्यक्रम का संचालन और उपस्थित गणमान्य

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉ. विश्वेश ठाकरे ने किया। आभार प्रदर्शन श्लोक ध्वनि फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य श्री कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि यह केवल पुस्तक विमोचन नहीं बल्कि क्रांतिकारी चेतना के पुनर्स्मरण का अवसर है जो नई पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति और इतिहासबोध की दिशा में प्रेरित करेगा।

इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख हस्तियों में शामिल थे इतिहासकार एवं पुरातत्वविद डॉ. रमेंद्र नाथ मिश्र, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, आकाशवाणी रायपुर से महेंद्र साहू, वरिष्ठ पत्रकार वैभव बेमेतरिहा, शिव प्रसाद मिश्रा, तथा श्लोक ध्वनि फाउंडेशन के सुमित शर्मा, अनिल तिवारी, नितेश पाटकर एवं भुनेश्वरी जायसवाल।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.